राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 31 | अंक 6 | जून 2010 | नई दिल्ली | मूल्य 5 रु. | पृष्ठ 32

ABVP
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ज्ञान • शील • एकता
1949-2009
60

एक आन्दोलन देश के लिए

9 जुलाई
विश्व विद्यार्थी दिवस

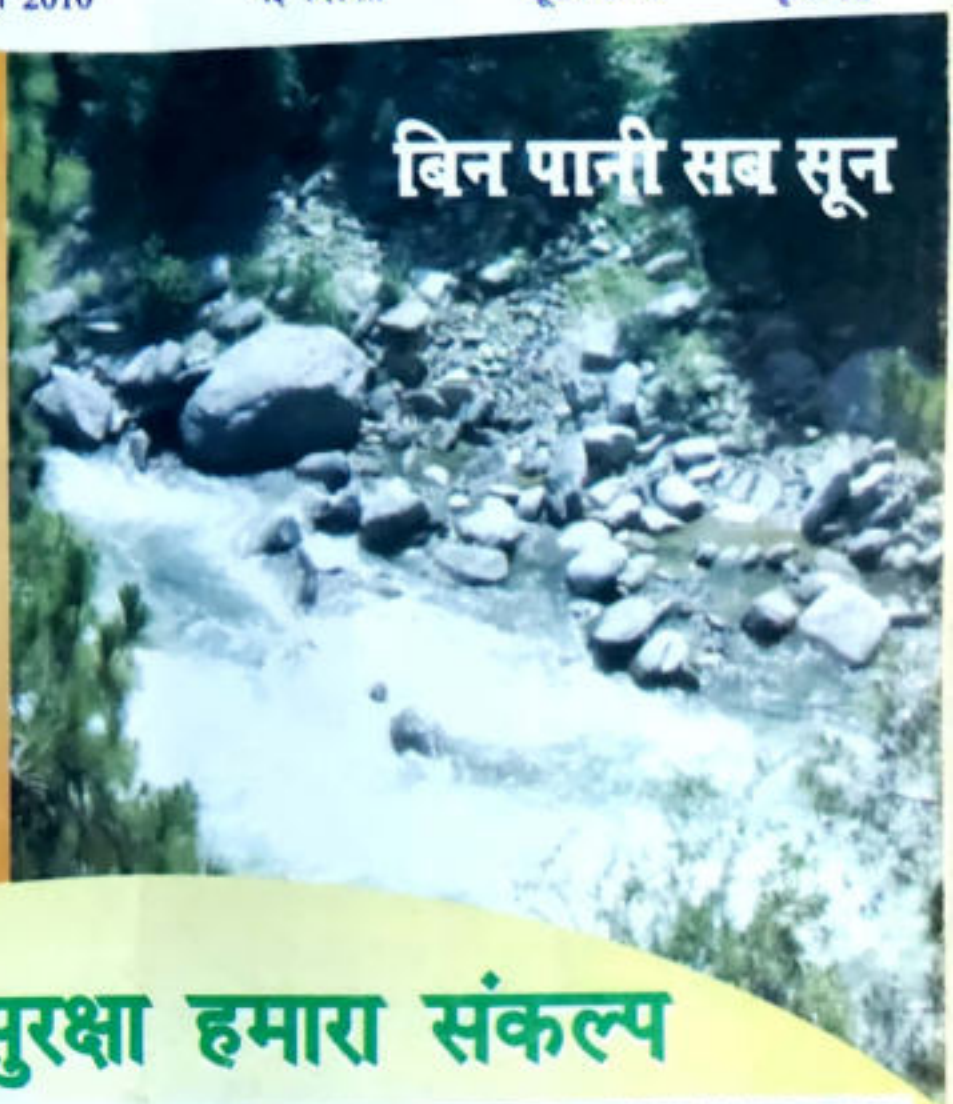

पर्यावरण सुरक्षा हमारा संकल्प

मेरठ में पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरूआत में साईकिल रैली निकालते अभाविप कार्यकर्ता

अमुवि में आरक्षण सम्बंधी संगोष्ठी में उपस्थित अतिथिगण

रंगनाथ मिश्रा आयोग पर आयोजित परिचर्चा में मंचस्थ राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री कुमार सुनील, पूर्व मंत्री मदन दिलावर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. राजीव सक्सेना। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र एवं गण्यमान्य जन

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए उत्तर क्षेत्र प्रचारक श्री कृष्ण गोपाल। साथ में हैं रा.स्व.संघ के प्रान्त संघचालक डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद एवं अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री रमाशंकर सिन्हा

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यजन

लखनऊ में बी.एड. की परीक्षा रद्द करने के विरोध में सड़कों पर उतरे अभाविप कार्यकर्ता

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक:
आशुतोष

सम्पादक मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011-43098248
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मुद्रक और प्रकाशक राजकुमार शर्मा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट कैम्पस, यूनिवर्सिटी एरिया, दिल्ली-110007 के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के.30 नवीन शहादरा, दिल्ली. 32 द्वारा मुद्रित

अनुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृ.सं.
सम्पादकीय		5
शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की घोषणा		6
पर्यावरण संरक्षण:भारतीय पक्ष	•डॉ. शिवबालक मिश्र	8
बिन पानी सब सून	•अमरनाथ बेगड़	13
पर्यावरण जागरूकता रैली		16
यह धरती कितना देती है।	•आशुतोष	17
9 जुलाई - विश्व विद्यार्थी दिवस	•गौरव शर्मा	19
नक्सल हमलों के विरोध में प्रदर्शन		20
अभाविप : स्थापना की पृष्ठभूमि	•डॉ. प्रदीप राव	21
सामाजिक विभेद का पर्याय रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट-*सुनील बंसल*		24
अमुवि में लागू हो आरक्षण-*कृष्ण गोपाल*		24
राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के संक्षिप्त प्रस्ताव		25
देश में एकात्मकता को बढ़ाने का एक प्रयास	•श्रीहरि बोरीकर	28
राष्ट्र मण्डल खेल : सज रही दिल्ली उजड़ रहे गरीब	•अवनीश सिंह	29

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

वर्षा और नदी

पानी, जब समुद्र से आता है,
तब बादल हो जाता है।
बादल उड़ती हुई नदी है,
नदी बहता हुआ बादल है।
बादल से वर्षा होती है,
वर्षा धरती की शालभंजिका है
उसके पदाघात से धरती लहलहा उठती है।
और जब वर्षा नहीं होती,
तो यही काम नदी करती है।
वर्षा और नदी- धरती की दो शालभंजिकाएं।
विचार और कर्म, कल्पना और यथार्थ,
आत्मा की शालभंजिकाएं हैं।
इनके पदाघात से
आत्मा पल्लवित-पुष्पित होती है।
बादल धरा पर उतर कर सार्थक होता है,
विचार कर्म में परिणत होकर कृतार्थ होता है।

संपादकीय

'आखिर इस धरती पर हम मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह जैसी थी, अगर जाते समय इसे कुछ और अच्छी न बना सकें तो कम-से-कम खराब करके तो न जायें। आने वाली पीढ़ियों का-और मां वसुन्धरा का-कुछ तो ख्याल करें'।

यह चिन्तन है एक पर्यावरण कार्यकर्ता का। वस्तुतः यह भारतीय तत्वदर्शन से निकला वह नवनीत है जिसे लेकर भारत का समाज चला। दृष्टा ऋषियों ने जिन सूत्रों को पाथेय के रूप में मानव को दिया वह विश्वमंगल का पूर्वाख्यान था। इन सूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की सामाजिक व्यवस्था भी भारतीय समाज ने विकसित की।

मानव ही नहीं, प्राणिमात्र भी नहीं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक अवयव को आदर देना, संघर्ष नहीं सहअस्तित्व का भाव जगाना, यह भारत का आदर्श ही नहीं बल्कि जीवनशैली का अविभाज्य अंग रहा है। पश्चिम के बढ़ते प्रभाव के कारण इसमें विक्षेप आया। जीवनशैली में आये बदलाव ने प्रकृति के सन्तुलन को बिगाड़ा। परिणाम सामने है।

भारत के संदर्भ में बात करें तो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र जैसी जीवनदायिनी नदियां आज अपनी पवित्रता खो बैठी हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल सिमट रहे हैं, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। जलवायु में अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं। वायु का प्रदूषण सीमा पार कर गया है। अपनी यह वसुन्धरा यदि हम सबका सरोकार है तो उसके रक्षण के लिए आगे आना ही होगा।

'छात्रशक्ति को राष्ट्रशक्ति' और 'आज के छात्र को आज का नागरिक' मानने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए भी यह परिस्थिति स्वाभाविक ही चिंताजनक है। हाल ही में उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में सम्पन्न परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक तापवृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। संगठन के उपस्थित पदाधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा देशभर में इसके लिए जनजागरण करने का निश्चय किया।

कार्यकारी परिषद् ने सरकार से शिक्षा के व्यापारीकरण को अस्वीकार्य बताते हुए नीतियों में परिवर्तन लाने, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की घातक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने तथा वर्तमान परिस्थिति पर चिंता जताते हुए नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाये जाने की मांग की। बैठक में पारित प्रस्ताव तथा विशेष कार्यवृत्त भीतर के पृष्ठों पर पढ़े जा सकते हैं।

पर्यावरण पर उपयोगी सामग्री इस अंक में रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री भी पाठकों के लिए विचारोत्तेजक सिद्ध होगी, यह विश्वास है।

आपकी प्रतिक्रिया अथवा सुझावों का स्वागत है। इन्हें पाठकों के पत्र में सम्मिलित करने का यथासम्भव प्रयास रहेगा।

शुभकामना सहित,

सम्पादक
आशुतोष

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक सम्पन्न

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की घोषणा

देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा के व्यापारीकरण के विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, नक्सली हिंसा के विरोध तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न रचनात्मक तथा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा संगठन ने की है। उक्त सभी निर्णय देहरादून, हिमालय में आयोजित परिषद की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में लिये गये।

शिक्षा के व्यापारीकरण के राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की शुरुआत 18 व 19 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित **देशभर के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में आये प्रतिनिधियों को मांग-पत्र सौंपने से होगी। इससे पूर्व सभी प्रदेशों में धरना व प्रदर्शन आयोजित कर जनजागरण किया जायेगा तथा राज्य के शिक्षामंत्रियों से मिलकर उन्हें संगठन की मांगों से अवगत कराया जायेगा। इस पर आगामी रणनीति बनाने के लिए जुलाई माह में एक अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन की भी योजना बनाई गई है।**

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् ने बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति पर चिन्ता प्रकट करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाने तथा जल संरक्षण के लिए देशभर में अभियान चलाने का भी निर्णय किया।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यजन

देश के विभिन्न भागों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करार देते हुए इसके विरुद्ध आन्दोलन करने के साथ ही केन्द्र सरकार से सच्चर समिति तथा रंगनाथ मिश्र समिति की अनुशंसाओं को रद्द करने की मांग करने का भी निर्णय किया।

बैठक में देश के आधे राज्यों में नक्सलवादियों के बढ़ते प्रभाव को चिंताजनक बताते हुए इस पर तुरन्त लगाम लगाने की माग की गई। समय रहते नक्सलवाद पर अंकुश न लगाने के लिए कार्यकारी परिषद् ने केन्द्र की वर्तमान संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

आगामी वर्ष के लिए संगठनात्मक योजना के अंतर्गत सदस्यता को बढ़ा कर 20 लाख तक पहुंचाने और 5 हजार स्थानों पर इकाइयां गठित करने तथा सम्पर्क स्थापित करने का लक्ष्य निश्चित किया है। देश के 10 हजार महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एकजुट कर शिक्षा के व्यापारीकरण के आन्दोलन को गति देने का निर्णय भी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में किया गया।

इससे पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिन्द मराठे व राष्ट्रीय महामन्त्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उद्घाटन सत्र के प्रारम्भ में दंतेवाड़ा में नक्सली हिंसा में शहीद 83 जवानों व नागरिकों के लिए एक

मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिन्द मराठे ने उत्तरांचल में संस्कृत को द्वितीय राज भाषा घोषित करने को विद्यार्थी परिषद् के आन्दोलन की सफलता बताया। श्री मराठे ने अवैध बंग्लादेशियों की उपस्थिति को भारत की सम्प्रभुता के लिए खतरा बताते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद् ने सम्पूर्ण भारत में अवैध बंगलादेशियों को चिन्हित करने तथा उन्हें वापस बंगलादेश भेजने की मांग केन्द्र सरकार से की थी तथा 17 दिसम्बर 2008 को समस्त भारत से पचास हजार कार्यकर्ताओं ने बिहार के किशनगंज चिकननेक बिहार में विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत में अवैध रूप से रह रहे 3 करोड़ बंगलादेशी घुसपैठियों के यूनीक आईडेन्टिटी कार्ड (UID) बनाने की आशंका जतायी क्योंकि इसको लेकर केन्द्र सरकार पर्याप्त गम्भीर नहीं है।

नक्सली हिंसा पर विद्यार्थी परिषद् का रूख स्पष्ट करते हुए प्रो. मराठे ने कहा कि देश के 14 राज्यों के 230 जिलों में फैला नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि आतंकवाद का ही एक रूप है। उन्होंने कहा कि नक्सलवादी पूर्णतया राष्ट्र विरोधी तत्व हैं तथा उनसे उसी प्रकार निपटा जाना चाहिए जिस प्रकार आतंकवादियों से निपटा जाता है।

पर्यावरण को प्रमुखता दें : प्रो. मेहता

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक के नागरिक अभिनन्दन समारोह में प्रख्यात पर्यावरणविद् श्री एम.सी. मेहताने अपने उद्‌बोधन में कहा कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा जो हमारी मां है उसे आज प्रदूषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा सरकारों की योजनाओं से नहीं हो सकती। समाज, विशेषकर युवाओं की भूमिका निश्चित होनी चाहिए। उन्होंने परिषद् कार्यकर्ताओं से वायु, जल की रक्षा हेतु संकल्प करवाया तथा अपने कार्यक्रमों में पर्यावरण के विषय को प्रमुखता देने की अपील की।

बढ़ते कदम

शिक्षा सत्र 2009-2010 में कुल सदस्यता 17,80,802 हुई हे जो गत सत्र की तुलना में 2 लाख अधि है। देश के लगभग 26 प्रदेशों में परिषद् की सदस्यता में इजाफा हुआ है, परिषद् का कार्य वर्तमान 3,371 स्थानों पर है जो पिछले वर्ष से लगभग 250 स्थान अधिक है। हिमालय के गर्भ लेह-लद्दाख से लेकर सुदूर अण्डमान निकोबार टापुओं पर भी परिषद् की सक्रिय इकाईयां हैं।

परिषद् द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में देशभर के 5000 महाविद्यालयों में सक्रिय इकाईयां खड़ी की गई हैं जो पिछले वर्ष 4200 थी। लगभग 800 महाविद्यालयों में परिषद् ने इकाईयों व कार्यक्रमों में बढ़ोत्तरी की है। देश के 558 जिलों में परिषद् की सक्रिय इकाईयां चल रही हैं। परिषद् के वर्तमान में 350 पूर्णकालिक कार्यकर्ता पूरा समय देकर परिषद् के कार्य को बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद् की सहायता देशभर के सभी कैम्पस, जिसमें सामान्य शिक्षा तकनीकि, मेडिकल के छात्रों में भी सदस्यता में बढ़ोत्तरी हुई है।

राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस (स्थापना दिवस 9 जुलाई) के कार्यक्रम इस वर्ष 2619 स्थानों पर हुए जिनमें 4,00,000 छात्रों ने भाग लिया।

सामाजिक समता दिवस- 6 दिसम्बर (डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुण्य तिथि) के कार्यक्रम 760 स्थानों पर किये गये। जिनमें 1,00,000 छात्र इसमें सहभागी हुए। युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के कार्यक्रम 2366 हुए जिसमें 396716 छात्रों का सहभाग रहा।

■

पर्यावरण संरक्षण : भारतीय पक्ष

■ डॉ. शिवबालक मिश्र

पृथ्वी के विषय में हमारे मनीषियों का चिन्तन बहुत ही प्राचीन, गहन और विस्तीर्ण होने के बाद भी आज भी प्रासंगिक है। यह चिन्तन केवल मानव जाति के इतिहास तक सीमित नहीं है बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी आयु, खनिज सम्पदा, जीव की उत्पत्ति और उसके विकास के विषयों को समाहित करता है। पर्यावरण का विषय इस चिन्तन में बार-बार आता रहा है। फिर चाहे पवित्र नदियाँ हो, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति और जन्तुओं की बात हो या फिर इनके साथ मानव के सम्बन्ध सूत्रों की चर्चा। हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है कि यह पृथ्वी लगभग 199 करोड़ वर्ष पुरानी है और इस पर 84 लाख जीव प्रजातियाँ निवास करती है। जैविक विविधता के विषय में इससे अधिक स्पष्ट वर्णन विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। आज का वैज्ञानिक भी केवल 30 लाख प्रजातियों की ही बात करता है। इस जैविक विविधता को संरक्षित रखने के लिए तथा स्वयं मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आज की अनिवार्यता है।

हमारे देश की मान्यता रही है कि यह शरीर क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर जैसे घटकों से बना है। और यही घटक हमें आवृत भी करते हैं। भारतीय विचारकों ने प्रतिपादित किया था **'यत् पिण्डे तदैव ब्रह्माण्डे'** अर्थात् जो शरीर के अवयव हैं वही बाह्य जगत में है। इसलिए पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर तभी तक स्वस्थ रह सकता है जब तक इन तत्वों का बाह्य जगत में सन्तुलन बना है। शरीर नष्ट होने को कहा जाता था **'पंचतत्व गतः'** अर्थात् शरीर के पाँचों तत्व बाह्य तत्वों में जाकर विलीन हो गए।

इन पंच तत्वों में जब हम क्षिति की बात करते हैं तो विविध प्रकार के शैल, उनके अपक्षय से बनने वाली मिट्टी और उस पर उगने वाली वनस्पति तथा रहने वाले जीव भी सम्मिलित होते है। जल हमारी पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के अन्दर पाया जाता है। पृथ्वी पर नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्र में तथा पृथ्वी के अन्दर भूजल के रूप में पाये जाने वाले जल को हमारे ऋषियों ने जीवन के नाम से सम्बोधित किया है। पावक हमारी पृथ्वी पर दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि के रूप में उपलब्ध है और गगन अर्थात् सौर उर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। समीर अर्थात् वायु हमारे शरीर के अन्दर और बाहर सदैव पाई जाती है। ये सभी घटक मनुष्य जीवन के आधार हैं। ये घटक वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल, शैल मंडल आदि के रूप में विद्यमान हैं।

प्राकृतिक चक्र

पर्यावरण के विभिन्न घटकों का चक्र अनवरत है। उदाहरण के लिए जल चक्र, वायु चक्र आदि। हमारे मनीषियों ने प्रकृति के इस चक्रिक व्यवहार का विषद अध्ययन किया था। उन्होंने ऋतुओं के चक्रिक व्यवहार के विषय में कहा था **'दिनमपि रजनीं सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायातः'**। इतना ही नहीं उन्होंने समय चक्र, जीवन चक्र और यहाँ तक कि पृथ्वी, सौर मंडल तथा ब्रह्माण्ड के चक्रिक व्यवहार की अवधारणा भी बतायी थी जो आज का वैज्ञानिक अब मान रहा है। यदि हम जल चक्र देखें तो समुद्र की सतह से पानी वाष्प बन कर वायुमंडल में जाता है। वहाँ से घनीभूत होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर गिरता है जिसका कुछ भाग पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है। कुछ भाग प्रतिवर्ष पृथ्वी के अन्दर समावेश होकर भूजल के रूप में अवस्थित हो जाता है- जैसे किसान अपनी फसल का कुछ भाग भंडारित करता है, और शेष भाग नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र तक पहुँच जाता है। यह जल चक्र सदैव चलता है। इसी प्रकार जब जल प्रवाह होता है अथवा तीव्र हवाएँ चलती हैं या फिर पर्वतों पर हिमनद प्रवाहमान होते हैं तो वे भूक्षरण करके मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाते हैं। यह मिट्टी और बालू आदि समुद्र में जाकर वर्षानुवर्ष परत दर परत जमा होती रहती है। अपने ही दबाव और उससे उत्पन्न ताप के कारण परतदार चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं परतदार तथा अन्य शैलों से पर्वतशृंखलाओं का निर्माण होता है। हिमालय का जन्म **'टिथिज सागर'** में हुआ है जो यूरोप के आल्पस क्षेत्र से लेकर वर्तमान म्यानमार तक फैला था। इस तरह सागर से पर्वत और पर्वत से मैदान और फिर सागर यह भी एक चक्रिक व्यवहार है।

कालान्तर में अत्यधिक दाब-ताप के परिणामस्वरूप

परतदार शैल परिवर्तित शैलों में भी बदल जाते हैं। और फिर भूक्षरण से आरम्भ होता है नया शैल चक्र। इसी प्रकार वायु, ताप तथा सौर उर्जा के भी चक्र चलते रहते है। प्रत्येक प्राकृतिक चक्र की एक निश्चित् अवधि होती है। ज्वार-भाटा प्रतिदिन आता है, वर्षा प्रतिवर्ष होती है, वृक्षों को बड़ा होने में 10 वर्ष तक लगते हैं और बालू मिट्टी को चट्टानों में बदलने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।

पर्यावरण असन्तुलन के खतरे

पर्यावरण का सन्तुलन तब बिगड़ता है जब मनुष्य इन प्राकृतिक चक्रों के साथ अधिक छेड़छाड़ करता है क्योंकि शरीर का निर्माण करने वाले और शरीर के बाहर पाये जाने वाले पंच घटक अन्योन्याश्रित हैं और पारस्परिक सन्तुलन बनाकर रखते हैं। यदि प्राकृतिक चक्र अपनी गति से चलते रहें तो कोई कठिनाई नहीं होती। यही कारण है कि जब इस पृथ्वी पर मानव आया तो उसे आदर्श रमणीक पर्यावरण मिला, न प्रदूषण था और न प्राणवायु की कमी थी। मानव ने केवल इसे हजार वर्षों में ही उस सौन्दर्य को क्षत-विक्षत कर दिया। वायुमंडल में कल-कारखानों के माध्यम से कार्बनडाइऑक्साइड अर्थात् धुएं की अनियंत्रित मात्रा छोड़ी जा रही है और यह विषपान करने के लिए वृक्ष नहीं होंगे तो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, हिमनद पिघलेंगे और समुद्र का जलस्तर ऊँचा उठेगा तो समुद्र के किनारे बसे नगरों पर जलमग्न हो जाने का संकट आएगा। वस्तुत: यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति के बाद पर्यावरण बहुत ही तीव्र गति से बिगड़ा है। असली समस्या है पृथ्वी के प्रति हमारे दृष्टिकोण की।

दासी या माता

मनुष्य अपने जीवन-यापन के लिए पृथ्वी से संसाधन प्राप्त करता है और प्राकृतिक चक्रों में कुछ हस्तक्षेप भी करता है। परन्तु यह हस्तक्षेप यदि केवल जीवन-यापन तक सीमित होता तो कठिनाई न होती। सभ्यताओं का संघर्ष जब आरम्भ हुआ, दूसरों पर आधिपत्य जमाने की होड़ मची। लूटमार की यह होड़ उन लोगों ने मचाई जिनका आध्यात्मिक स्तर बहुत नीचा था, परन्तु शस्त्रास्त्रों की क्षमता बहुत अधिक थी। वे लोग पृथ्वी का जीवन काल बहुत छोटा मानते थे और उनकी एक जन्म की अवधारणा रही है। पश्चिमी लोगों का मानना था कि इस धरती का जन्म ईसा से 5 हजार वर्ष पहले हुआ था जब कि मध्य एशिया के लोगों की मान्यता रही है कि चौहदवीं सदी में कयामत आएगी और यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। इन लोगों का मानना था कि समय कम है इसलिए परमेश्वर ने इस धरती पर जो कुछ नियामत बख्शी है उसे जल्दी से खा लो, भोग लो। पश्चिमी विचारधारा के लोगों में प्रकृति पर विजय पाने और उसे दासी बनाने की होड़ सी लग गई और इसका परिणाम हुआ प्रकृति का विद्रूपण और विनष्टीकरण।

इसके विपरीत भारत के लोगों की मान्यता रही है कि पृथ्वी से हमारा नाता बहुत ही पुराना है। यह पृथ्वी न तो इतनी नई है और न इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। भारत के लोगों ने पृथ्वी के साथ अपना नाता परिभाषित करते हुए कहा था **'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:'**। जब तक यहां के लोग पश्चिमी प्रभाव में नहीं आए थे, पृथ्वी के प्रति मातृवत व्यवहार करते रहे। जब तक यहां की धरती शस्य श्यामला थी, रमणीक वन थे, नदियों में शीतल शुद्ध जल था। यहां के लोग सहज भाव से शान्त और धैर्यवान हुआ करते थे। अब हमारे देश और समाज का जीवन-दर्शन और जीवन शैली बदल रही है। उसी के अनुरूप प्रकृति और प्राणी का सम्बन्ध भी परिभाषित हो रहा है। सोचने का विषय यह है कि इस धरती और प्रकृति के साथ दासी जैसा व्यवहार करेंगे अथवा माता तुल्य।

भोगवादी संस्कृति

मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं में प्राय: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, औषधि को ही गिनाया जाता है क्योंकि इनको अर्जित करके प्राप्त किया जाता है। इन सब से भी अधिक आवश्यक है सांस लेने के लिए प्राणवायु और पीने के लिए शुद्ध जल। जल के माध्यम से ही स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और श्वासोच्छ्वास के माध्यम से प्राणवायु रक्त को शुद्ध करती है और कार्बनडाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस शरीर से बाहर निकलती है। भारत के लोगों ने प्राणायाम के विविध प्रयोगों द्वारा जलवायु के इस महत्व को ठीक प्रकार समझा था। स्वस्थ शरीर और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करने के लिए जिस पर्यावरण की कल्पना उन्होंने की थी उसका वर्णन यजुर्वेद में कुछ इस प्रकार किया गया है:

उपहरे गिरीणाम् संगमे च नदीनाम्
धिया विप्रो अजायत।

अर्थात् पर्वतों के समीप और नदियों के संगम स्थान पर तथा अन्य पवित्र स्थानों में अपने साधन और श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। इस ब्राह्मणत्व का जात-पात से कुछ लेना-देना नहीं है। यह तो श्रेष्ठ मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए उपयुक्त परिवेश की बात थी। जन-सामान्य को स्वस्थ रखने और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए समय-समय पर विद्वतजनों की गोष्ठियां हुआ करती थीं। ऐसी ही एक गोष्ठी ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में हिमालय क्षेत्र में ऋषि भरद्वाज के आश्रम में सम्भवत: अल्मोड़ा के पास हुई थी। इसके विषय में बताया गया है:

तदा भूतेष्वनुकोशं पुरुस्कृत्य महर्षय:।
समेता पुण्य कर्माण: पार्श्वे हिमतव: भुमे॥

हिमालय क्षेत्र में सम्पन्न हुई यह गोष्ठी चिकित्सा विज्ञान की विश्व की प्रथम गोष्ठी थी। ऐसी ही गोष्ठियों के माध्यम से मनीषियों ने शारीरिक विकास के लिए आवश्यक भोजन के प्रमुख अवयवों को परिभाषित किया था। आज इन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड, वसा, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन के नाम से जानते हैं।

परन्तु इन स्थूल अवयवों के साथ-साथ हमें सूक्ष्म मात्रा में तांबा, जस्ता, लोहा, स्वर्ण, कैल्शियम आदि भी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इसका ज्ञान भी हजारों वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया था। इन पदार्थों को भस्म, आसव, अरिष्ट, अवलेह आदि के रूप में प्रयोग करते थे, परन्तु सावधान भी करते थे कि अति सर्वत्र वर्जयत्। पर जिनके पूर्वजों ने बताया था **'भोगे रोग भयं'** वे भी आज भोगवादी संस्कृति के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं।

भोगवादी संस्कृति का एक उदाहरण मांसाहार के रूप में हमारे सामने आता है। इस विषय में कुछ आंकड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- सोलह किलोग्राम अन्न पशुओं को खिलाकर अमेरिका में एक किलोग्राम मांस प्राप्त होता है।
- एक एकड़ भूमि में 100 क्विंटल आलू पैदा किया जा सकता है और यही भूमि यदि मांस हेतु पशु आहार उत्पादन में प्रयोग हो तो एक क्विंटल से भी कम मांस मिलेगा।
- मांसाहारीआबादी की अपेक्षा यह पृथ्वी दस गुना से भी अधिक शाकाहारी आबादी का भार वहन कर सकती है। यह तथ्य भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- मांसोत्पादन में अन्नोत्पादन की अपेक्षा 100 गुना अधिक पानी व्यय होता है।
- लागत की दृष्टि से देखें तो मांसाहारी प्रोटीन की कीमत शाकाहारी प्रोटीन से कम से कम 10 गुना अधिक है।
- स्वास्थ्य की दृष्टि से मांसाहार की अपनी समस्याएं हैं, जिन्हें आज पश्चिमी वैज्ञानिक भी जानते और मानते हैं।

भारत में जीवन वध का विरोध करने वाली सांस्कृतिक धारा ही इस देश की मुख्य धारा थी। तभी तो कबीरदास जी वृक्षों का वध करने वालों और पशुवध करने वालों को फटकारते हुए कहते हैं:

बकरी पाती खात है, ताकी खींची खाल।
जे बकरी को खाल हैं, तिनके कौन हवाल॥

लकड़कट्टा संस्कृति

एक समय था जब भारत में हरे पेड़ काटने वालों को लकड्कट्टा कहा जाता था। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। उनके घर में लोग पानी नहीं पीते थे। आज भी यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मालूम हो जाएगा कि आरा मशीनों के मालिक कौन हैं, बूचड़खाने चलाने वालों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है और भारत में दया-क्षमा के स्थान पर क्रूरता और संवेदनहीनता कहां से आ गई। विचार कीजिए कि जब बकरा, भैंसा अथवा मुर्गे का गला थोड़ा सा काटकर तड़पने के लिए छोड़ा जाता है और बच्चे आनन्दपूर्वक देखेंगे, फिर पशु शरीर से सारा रक्त बह जाने के बाद उसका गला काटा जाएगा और यह सारा दृश्य नन्हा बालक देखेगा तो उसके कोमल मस्तिष्क पर कौन से संस्कार अंकित होंगे? मैं किसी मजहब की बात नहीं करता। मैं केवल बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करता हूं। जब यह दशा है पशुओं की तो वृक्षों पर कौन दया करेगा।

ठंडा रेगिस्तान बनने का खतरा

वृक्षों में जीवन है यह बात भारत के लोग हजारों वर्षों से जानते और मानते थे। यही कारण है कि जब श्री जगदीश चन्द्र बसु ने प्रयोग करके आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में विश्व को बताया कि पेड़ों में प्राण होते हैं तो इस देश में शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ होगा। यहां तो वृक्षों की तुलना भगवान शंकर से की जाती रही

है। और कितनी सार्थक है यह तुलना क्योंकि मानव कल्याण के लिए शिव ने हलाहल का पान किया था और ये वृक्ष मानव-कल्याण के लिए कितनी मात्रा में कार्बडाइऑक्साइड रूपी विषपान करते हैं और बदले में देते हैं अमृत तुल्य प्राणवायु। ऐसे वृक्ष रूपी मित्रों के साथ कृतघ्नता की सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं। जंगल माफिया केवल हिमालय और उसकी तराई के ही नहीं मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे शान्त बैठे इन मित्रों को नेस्तनाबूद कर चुके हैं। हिमालय के क्षेत्र में वनों की कटाई से तो आपदाओं का अम्बार लग गया है। पेड़ जो अपनी जड़ों से मिट्टी की सतह को सुदृढ़ बनाते थे, भूजल के लिए अधोगमन का मार्ग बनाते थे, पत्तियों से मिट्टी को उर्वरा बनाते थे, पशुओं के लिए चारा और ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करते थे, अब नहीं रहे। निर्वनीकरण की यह दशा है कि पर्वत शृंखलाएं बिल्कुल नंगे सिर वाली हो गई हैं, उन पर वर्षा जल अबाध गति से बह जाता है, भूक्षरण करता है जिससे तमाम उपजाऊ मिट्टी नदियों के माध्यम से बह जाती है और बच जाती है पथरीली अनुपजाऊ भूमि। धीरे-धीरे हिमालय क्षेत्र ठंडे रेगिस्तान में बदल रहा है।

वृक्षों की रक्षा जरूरी

पहाड़ की महिलाएं जंगल को अपना मायका कहती हैं। क्योंकि वे वहां से जलाने के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारा जब आवश्यक होता है, ले आती हैं। यही कारण है कि महिलाओं ने चिपको आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया था। भारत में वृक्षों की रक्षा का यह पहला आन्दोलन नहीं था। इसके बहुत पहले राजस्थान के बिश्नोई सम्प्रदाय के लोगों ने वृक्षों से चिपककर बड़ी संख्या में प्राणाहुति देकर वृक्षों की रक्षा की थी।

पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के अत्यधिक कटान और बहाव के कारण अनेक बार नदियों के मार्ग में मलवा जमा हो जाता है और उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, बाढ़ आती है और भूस्खलन होते हैं। इन सबके विस्तार में जाना सम्भव नहीं परन्तु इनके लिए उत्तरदायी हैं जंगलों का कटान, पर्वतीय क्षेत्रों में अविवेकपूर्वक सड़कों का निर्माण, यातायात के लिए भारी वाहनों का प्रयोग, ऊंचे भवनों का निर्माण, अविचारित पर्यटन सुविधाएं, बकरी पालन और कुछ हद तक बहुद्देशीय भारी परियोजनाएं। पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाली टिहरी, झमरानी, धौलीगंगा आदि अनेकानेक परियोजनाओं के विवाद में मैं इस समय नहीं जाना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि इन परियोजनाओं के विषय में जो कोहराम इस समय मचा है वह परियोजनाएँ आरम्भ होने और अरबों रुपया व्यय होने के पहले ही मचना चाहिए था।

जल संकट

वैसे तो सारे विश्व में जल संकट छाया हुआ है परन्तु भारत में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो जलाभाव की तथा दूसरी जलप्रदूषण की। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के अन्दर भूजल के रूप में जल का संचय और भंडारण बहुत कम हो रहा है और व्यय बहुत अधिक है। पीने के लिए जिस भूजल का उपयोग होना चाहिए था उसका सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए और औद्योगिक इकाइयों के द्वारा हो रहा है। परिणामतः कुछ स्थानों पर तो एक मीटर प्रतिवर्ष की गति से भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। प्राचीन भारत में सिंचाई तथा पशुधन के उपयोग के लिए जलाशयों, झीलों, नदियों और तालाबों का पानी प्रयोग में लाया जाता था और पीने के लिए कुओं के माध्यम से भूजल का उपयोग होता था। अब तालाब मिट्टी से भर गए हैं, उनमें जलकुम्भी और शैवाल भरा है तथा उनमें जलभण्डारण सम्भव नहीं। इन तालाबों की चिन्ता न करके कभी तो 'पानी के खलिहान' अर्थात् वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है तो कभी कृत्रिम विधि से ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज की चर्चा चलती है। दोनों ही जोखिम भरे काम है और परिस्थिति को विषमतर बनाएंगे। जलाभाव के साथ ही जल प्रदूषण की समस्या कम भयावह नहीं है। आज पश्चिमी सभ्यता और औद्योगीकरण का परिणाम है कि पवित्र नदियों में सीसा, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक आदि विषैले पदार्थ बढ़ते जा रहे हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में जल संकट और भी भयावह है। वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को जल प्रपातों, स्रोतों और नालों के माध्यम से शुद्ध पेयजल अनादि काल से मिलता रहा है। झीलों का पानी प्रदूषित हो रहा है और वहां की महिलाओं को दूर घाटियों में मीलों चढ़ाई उतर कर पेय जल लाना पड़ता है। इस समस्या के लिए भी लकड़कट्टा संस्कृति उत्तरदायी है क्योंकि निर्वनीकरण के फलस्वरूप वहां की ढलान पर वर्षा जल की प्रवाह गति तीव्र हो जाती है और उसे भूमि प्रवेश का समय ही नहीं मिलता, वह बह जाता है तथा स्रोतों के रूप में निकलने के लिए भूजल संग्रहीत होता ही नहीं।

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण के विविध आयाम है। उनमें से एक है ग्रीन हाउस गैसों का अबाध उत्पादन। आजकल ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत में हो रहे छेदों की बहुत अधिक चर्चा हो रही है। क्योंकि यह छेद पश्चिमी देशों के आकार पर देखे गए थे और इससे सर्वाधिक कष्ट गोरी और मुलायम चमड़ी वालों को ही होने वाला है। यहां पर उल्लेखनीय है कि ओजोन नामक गैस की परत वायुमंडल के ऊंचे भागों को आच्छादित किए हुए है और जीव मंडल को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह गैस प्राणवायु के तीन परमाणुओं से बनी होती है जब कि ऑक्सीजन में प्राणवायु के दो परमाणु हाते हैं। जब ग्रीनहाउस गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरा कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी की सतह से उठकर वायु, वायुमंडल के ऊपरी भाग में पहुंचती हैं तो ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसे नष्ट कर देती है। इनमें से सर्वाधिक घातक है क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो एअरकंडीशनर्स, रेफ्रीजरेटर्स, और फ्रिजों में प्रयोग होती है। जब से यह तथ्य उजागर हुए हैं तब से पश्चिमी देशों ने अपना शिल्पविज्ञान बदल लिया है। परन्तु जो संयंत्र बने पड़े हैं उन्हें विकासशील देशों को बेचा जा रहा है। यह आपदा शुद्ध रूप से पश्चिमी सभ्यता की देन है।

वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई दूसरी समस्या है पृथ्वी तल पर अम्लीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फरडाइ ऑक्साइड आदि का अधिक मात्रा में उत्पादन। ये गैसें वायुमंडल में जाकर वर्षाजल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। इनमें विशेषकर कार्बनडाइऑक्साइड के बढ़ने से वायुमंडल का तापमान भी बढ़ता है। इसी प्रकार आणविक संयंत्रों, खनिजों तथा धातुओं के दोहन, विषैले रसायनों के प्रतिष्ठानों तथा शराब के कारखानों से निकलने वाली गैस तथा कचरा के कारण जल और वायु दोनों ही प्रदूषित होते हैं। कष्ट की बात यह है कि इन सबका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा कम और निर्जीव वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा अधिक होती है। उदाहरण के लिए मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली गैसों का ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चिन्ता तो सभी को है लेकिन उन गैसों का मनुष्य के फेफड़ों पर क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा नहीं होती।

इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण भी एक गम्भीर समस्या बन गई है। मोटर गाड़ियों, कल-कारखानों की मशीनों और पूजास्थलों पर लगे ध्वनिविस्तारकों के कारण अस्पतालों के मरीजों, तनावग्रस्त प्राणियों और जल सामान्य का भी जीवन कष्टमय हो गया है। यहां भी कबीरदास जी याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि कंकड़-पत्थर जोड़कर पूजास्थान बना लिया और उस पर चीख मचा रहे है मानो परमेश्वर बहरा हो गया हो। पर्यावरण की ये समस्याएं कुछ तो पुरानी हैं और कुछ विकास के विविध आयामों की देन है। हमें इतिहास से सीख लेनी ही चाहिए।

इतिहास का सन्देश

इतिहासकारों ने प्राचीन सभ्यताओं के विलुप्त होने का वर्णन करते समय उनके अक्षम नेतृत्व, सैन्य बल की कमी, सामरिक पराजय, महामारियों का प्रकोप और जलवायु में परिवर्तन आदि कारकों की चर्चा तो की है परन्तु मिट्टी, वन, जल प्रबन्धन, सिंचाई, मृदा अपक्षय आदि विषयों के साथ शासन-व्यवस्था को न तो जोड़ने का प्रयास किया है ओर न इनकी भूमिका का उल्लेख हुआ है। विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं में ग्वाटेमाला की टिकाल सभ्यता, पीरू की चैन सभ्यता, मैक्सिको की माया सभ्यता और मध्यपूर्व की बेबिलान सभ्यता उल्लेखनीय है। मध्यपूर्व की बेबिलॉन सभ्यता के समय सिंचाई की नहरों का जाल बिछा था। हरियाली, खुशहाली और सम्पन्नता थी। वहां की नहरें बालू मिट्टी से इसलिए भर गई कि ऊंचे भागों में जंगलों का अत्यधिक कटान और मृदा अपक्षय हुआ। इस प्रकार सीरिया, ईराक, लेबनान और तुर्की की भूमि और जलवायु के लिए स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है।

मध्ययुग में स्पेन एक समुद्री महाशक्ति बन गया था परन्तु जहाजों के बनाने में स्पेन वासियों ने इतने जंगल काट डाले कि स्पेन वीरान हो गया। मेक्सिको की माया सभ्यता इसलिए विलुप्त हुई कि वहां की धरती में इतनी धारक क्षमता नहीं थी कि वह अत्यधिक आबादी का पोषण कर सकती। इतिहास का यही सन्देश है कि जो सभ्यताएं प्रकृति सुन्दरी की गोदी में खेलती रहेंगी वही भविष्य में पल्लवित और पुष्पित होंगी। भारतीय मानसिकता, आस्थाएं और जीवन शैली में बिगड़ते पर्यावरण की चुनौतियों को झेलने की अन्तर्शक्ति विद्यमान है। ■

बिन पानी सब सून

■ अमरनाथ बेगड़

अजीब है यह पानी। इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इन्द्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर निनाद दूर-दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्नत शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसका शांत रूप भी भयाक्रांत करता है। जीवनदायी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है तो विनाशकारी वर्षा का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है यह पानी।

सौर मंडल में सबसे अच्छी जगह हमारी पृथ्वी को मिली है। कुछ ग्रह पृथ्वी से बड़े भले ही हों, किन्तु जीवन केवल पृथ्वी पर है, इसलिए क्योंकि यहां पानी द्रव के रूप में उपलब्ध है।

पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूपों में उपलब्ध है- वाष्प, द्रव और ठोस। यदि पृथ्वी सूर्य के ज्यादा निकट होती तो वह इतनी गर्म होती कि पानी केवल भाप के रूप में होता। ज्यादा दूर होती तो इतनी सर्द होती कि पानी केवल बर्फ के रूप में होता। दोनों ही स्थितियों में जीवन सम्भव न था। भाप और बर्फ पानी के ही रूप हैं लेकिन जीवन को वे रूप स्वीकार्य नहीं। संस्कृत में पानी को जीवन कहते हैं। कैसा सार्थक शब्द।

अन्य ग्रहों के पास पानी नहीं, इसलिए जीवन भी नहीं। मान लीजिए पृथ्वी दो होतीं, तो उस पृथ्वी पर भी पानी होता, जीवन भी होता। पास होने के कारण दोनों के बीच लोगों का आना-जाना भी होता, रोटी-बेटी का व्यवहार भी होता। किसी की ससुराल यहां तो किसी का मायका वहां। काश! हमारी धरती जुड़वां पैदा हुई होती।

जीवन का आरम्भ समुद्र से

गांवों और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भुला ही बैठा है। इसका सही अंदाजा तभी लग सकता है जब वह किसी लम्बी समुद्री यात्रा पर निकल जाये। चारों ओर जल का अनंत विस्तार। पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनियां पानी की दुनियां है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। जमीन पर रहते यह बात उसकी समझ में नहीं आती। हममें से अधिकांश की जिंदगी ऐसे बीत जाती है मानो समुद्र का अस्तित्व ही न हो।

पृथ्वी जब सूर्य से छिटक कर अलग हुई थी तो आग का गोला थी। खरबों वर्षों के बाद जब ठंडी हुई तो दो हिस्सों में बंट गयी-समुद्र और जमीन। समुद्र के खौलते पानी को ठंडा होने में लाखों वर्ष लग गये। तब इन्हीं समुद्रों की तली में जीवन का प्रादुर्भाव हुआ-सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में। ये जीवाणु ही वनस्पति, कीट-पतंग, जीव-जन्तु, पशु-पक्षी का आकार लेते-लेते अंत में मनुष्य के रूप में विकसित हुए। हम समुद्र से आये हैं, इसके प्रमाण आज भी हमारे शरीर में मौजूद है-

हमारे शरीर में भी तीन भाग जल है। बिल्कुल वही अनुपात। हमारा हृदय धड़कता है, समुद्र गरजता है। कहीं समुद्र का गर्जन धरती के हृदय की धड़कन तो नहीं!

तमाम जीवन का, इसलिए मनुष्य का भी, आदि निवास समुद्र है। संभवतः इसीलिए समुद्र हमें जितना उद्वेलित और सम्मोहित करता है उतना और कोई नहीं। पुरी का समुद्र देखकर चैतन्य महाप्रभु इतने भाव-विभोर हो गये कि उसी में समा गये।

समुद्र आज भी हमारा पालन-पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं कि समुद्र-मंथन से एक बार ही अमृत निकला था। अमृत हर साल निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है।

मानसून

सूर्य की गर्मी से तप कर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकार भाप ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाती है। इन बादलों को सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर तक हवाएं ले जाती हैं।

हमारे देश में जो हवाएं दक्षिण-पश्चिम से समुद्र की भाप से बने बादलों को लेकर आती हैं और वर्षा लाती हैं, वे हवाएं ही मानसून हैं। भारत में मानसून का आगमन दो दिशाओं से होता है। पश्चिम से आने वाला मानसून हिमालय तक जाता है और दिल खोलकर बरसता है। पूर्व से आने वाला पूर्व भारत को सींचता है।

अक्तूबर आते-आते मानसून का खेल खत्म हो जाता है।

वर्षा

जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। मेघ मानो इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने जीवन को सार्थक करने का समय मानो आ पहुंचा है। लोक कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने की घड़ी आ गयी है। यह कोई यात्रा करने के लिए यात्रा नहीं थी। आकाश में मंडराते रहना ही उनका उद्देश्य नहीं। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना, समुद्र ने जो धन उसे सौंपा उसे धरती को सौंप देना है। यही तो है वह मिशन जिसके लिए समुद्र ने उसे भेजा था। अगर वह बरसता नहीं तो उसका फेरा बेकार जायेगा।

पहले छोटी बूंदें, फिर मूसलाधार वृष्टि। झकोर-झकोर कर बरस रहे हैं बादल। बिजली भी कड़कती है। पौधे झुक-झुक रहे हैं। वृक्ष डोल रहे हैं। आकाश से इतना सारा पानी कैसे बरस सकता है? बादलों ने इतना सारा बोझ कैसे उठा रखा होगा? फटते बादलों के बीच लुका-छिपी का दृश्य कितना मोहक लगता है। रही-सही कमी इन्द्रधनुष पूरी कर देता है।

वर्षा ऋतु का आकाश-यानी आर्ट गैलरी। बादल ऐसे-मानो आकाश पर टंगी कलाकृतियां। जीवन से धड़कती, ऊपर से कूदती, नदी-नालों को छलकाती, धरा को शीतलता प्रदान करती, मैदानों को हरा-भरा करती और अपने आप को निछावर करती सजीव कलाकृतियां।

वर्षा यानी विराट नाट्य-प्रस्तुति। पहला अंक खेला जाता है समुद्र में, दूसरा आकाश के मंच पर और तीसरा धरती पर। वर्षा का फलक कितना विशाल है। पहले असीम सागर, फिर अतल आकाश और अंत में विस्तृत धरती। लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैला मंच। कितने घनिष्ठ हैं आकाश और पृथ्वी के बीच के बंधन।

प्राचीन काल में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर आधारित थी। एक वर्षा से दूसरी वर्षा तक के समय को लोग वर्ष मानते थे। वर्ष शब्द वर्षा से बना है। इजिप्ट में वर्षा नहीं होती। वहां की कृषि नील नदी की बाढ़ पर आधारित थी। वे एक बाढ़ से दूसरी बाढ़ तक के समय को वर्ष मानते थे। वर्षा और बाढ़ ने पंचांग को जन्म दिया है।

नदी

पानी का चंचल रूप है नदी। यह वह जीवन-रेखा है जो अपने कछार में बसे लोगों को जीवनदायी जल प्रदान करती है। जिस भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती होती है उसे देव मातृक और जो जमीन केवल वर्षा के भरोसे न रहकर नदी के पानी से सिंचित होती है उसे नदी मातृक कहा गया है।

नदी के कारण कृषि सम्भव हुई। जो शिकारी था, वह किसान बन गया। वह एक जगह घर बसा कर कला, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और साहित्य की ओर अग्रसर हो सका। मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया।

हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खिंचता चला आया है। केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है। बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है।

अंत में नदी समुद्र में जा मिलती है। पानी जहां से चला था वहीं पहुंच गया। नदी कभी समाप्त न होने वाली एक निरंतर रचना है। एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है।

समुद्र से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से नदी, नदी पुनः समुद्र में, जलवृत्त चलता रहता है। वर्षा की हर बूंद जो जमीन पर गिरती है, तीन से पांच साल के भीतर कुंओं में से बाहर आ जाती है और हमारे द्वारा पी ली जाती है। आज जो पानी है, वह अरबों साल पुराना है। हमारा पुनर्जन्म में विश्वास हो या न हो, पानी का है।

नदी के पानी की छैनी बड़ी पैनी होती है। कई दर्रे नदियों द्वारा निर्मित हुए हैं। पानी जैसी विनम्र वस्तु भला फौलाद सी कड़ी चट्टान को कैसे काट लेती है? दरअसल काटने-तराशने का काम केवल पानी नहीं करता। ज्यों-ज्यों नदी आगे बढ़ती है, वह जमीन के क्षार और अम्ल भी साथ लिये चलती है। काटने का काम अम्ल करता है। नदी के पानी में रेत के बारीक कण भी रहते हैं। ये भी चट्टानों को खुरचते रहते हैं। प्रवाह जितना तेज होगा, क्षरण भी उतना ही तीव्र होगा।

बांध

हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी के तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता था। नदी का पानी उफन पड़ता और तट-बंधों को तोड़ता गांव के गांव बहा ले जाता। जान-माल को भारी नुकसान पहुंचता। गांव पानी से घिर जाते या एक-दूसरे से अलग पड़

जाते, ढोर-डंगर बह जाते। लोग पेड़ों पर चढ़कर जान बचाते।

अकाल भी पड़ता। मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और दरकी-सूखी धरती-सभी पानी के लिए तरसते। हजारों लोग प्यास और भूख से तड़प-तड़प कर मर जाते। जानवर अलग मरते, धरती पत्थर बन जाती।

आदमी और नदी के बीच यह लड़ाई चलती रहती। कभी एक पक्ष की जीत होती, तो कभी दूसरे पक्ष की। लोग अपने घरौंदे बनाते और नदी उन्हें नष्ट कर देती। लोग इस लड़ाई से उकता गये। आखिर उन्होंने नदी पर बांध बनाना सीख लिया। हजारों वर्षों से मनुष्य पानी का संग्रह करता आया है-कुओं, तालाबों और बावड़ियों के रूप में। बांध उसी श्रृंखला में नयी कड़ी है।

पानी का परिवार

समुद्र-पानी का पितृ-पुरुष है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97 प्रतिशत पानी समुद्र में है।

हिम-2 प्रतिशत पानी हिम और हिमनद के रूप में है। ये पृथ्वी के 11 प्रतिशत धरातल को ढकते हैं। नदियों की तरह हिमनदों का प्रवाह भी संकरी घाटियों में तीव्रतम होता है। हिमनद अगर गतिशील न होते तो पृथ्वी की अधिकांश नमी बर्फ के विशाल पर्वतों में स्थायी रूप से कैद रहती और विश्व एक मरुस्थल होता। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो अचानक नये-नये झरने नजर आते हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है।

भूमिगत जल-अब बचा एक प्रतिशत पानी। इसका आधे से अधिक पानी जमीन के अन्दर है। निरंतर दोहन से भूगर्भ जल की सतह लगातार नीचे जा रहा है, जमीन के भीतर का तालाब खाली होता जा रहा है।

ताजा पानी-अब आधा प्रतिशत से भी कम पानी बचा है। यही है हमारा ताजा या मीठा पानी। पृथ्वी के समस्त पानी की कल्पना यदि हम एक गैलन (लगभग 4.5 लीटर) से करें तो इस ताजे-मीठे पानी की मात्रा इसके अनुपात में एक चम्मच से कुछ ज्यादा है। हमें इसी पर गुजर करना है।

आर्द्रता-आर्द्रता के कारण ही दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाता। रेगिस्तान की हवा में आर्द्रता नहीं होती। इसलिए रेगिस्तान में दिन का तापमान जहां 100 फैरन हीट होता है वहीं रात का तापमान इतना गिर जाता है कि अगर पानी हो तो बर्फ बन जाये। यह आर्द्रता ही है जो दिन की गर्मी को रात में भी धारण किये रहती है इसलिए रात बेहद ठंडी नहीं हो पाती।

कुहरा-कुहरा जमीन के निकट बना बादल है। यह तब निर्मित होता है जब आर्द्रता हो, हल्की बयार हो और विपरीत तापमान हो-गरम और ठंडा। ठंडी बयान जब गुनगुने पानी के ऊपर से गुजरती है तो कुहरा बनता है।

ओस-वातावरण में वाष्प रूप में मौजूद जल अक्सर रात में ठंडा होने पर छोटी-छोटी बूंदों के रूप में गिरता है। ठंड में गिरती ओस खेतों के लिए सिंचाई का काम करती है। कवियों ने इसे सौन्दर्य का प्रतिमान बना दिया है।

परम विलायक

ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इस सादे ढ़ांचे को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। जो भी चीज इसके सम्पर्क में आयेगी, घुलने लगेगी। शुद्ध जल नाम की कोई चीज नहीं। यदि प्रयोगशाला में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन के मिश्रण से शुद्ध जल बनाया जाय तो वह भी शुद्ध नहीं होगा। उसे किसी न किसी पात्र में रखना होगा। उस पात्र का कुछ अंश-कुछ अणु- घुलकर जल में आ जाएंगे। गिलास में जब आप पानी पीते हैं तो गिलास का कुछ अंश भी पीते हैं। हालांकि यह मात्रा हानिकारक नहीं होती। इसीलिए कई लोग उषा पान के लिए तांबे के लोटे में रखे पानी का उपयोग करते हैं।

मैल भी पानी में घुलता है और निकल जाता है। इसी गुण के कारण पानी हर तरह की गंदगी को साफ कर देता है। किन्तु इसके नुकसान भी हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी घुलकर आ सकती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है।। इस गुण के चलते ही पानी आसानी से प्रदूषित हो जाता है।

नदियां और प्रदूषण

आज संसार में जटिल से जटिल और खतरनाक रासायनिक पदार्थ पैदा हो रहे हैं। इन्हें इधर-उधर फेंकने या नदियों में बहा देने के घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। कल-कारखानों के अलावा बड़े शहर भी अपना मल-मूत्र नदियों के हवाले करते हैं। खेतों में किसान जिन कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, देर-सबेर वे भी नदियों में पहुंचते हैं। इनमें से कुछ जहरीले रसायन

बरसों बाद भी प्रभावहीन नहीं होते। अमरीका में डीडीटी पावडर पर प्रतिबंध लगने के बीस बरस बाद भी वह मिसीसिपी नदी के पानी में पाया गया।

मिसीसिपी में ही पकड़ी टनों मछलियां इसलिए नष्ट कर देनी पड़ी क्योंकि उनके शरीर में पीसीबी नामक जहरीला रसायन पाया गया। पेलिकन जैसे पक्षी जो इन मछलियों को खाते थे, वे भी मर गये। ये रसायन भोजन के साथ मनुष्य के शरीर में और मां के दूध के साथ शिशु के शरीर में पहुंचते है। नदी में प्रदूषण के कारण उत्पन्न वायरस हैजा, टायफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं।

दूषित पेय-जल देश में, विशेष रूप से गांवों में फैलने वाले रोगों का विशेष कारण है। जहरीले रसायनों के कारण पानी का एक बड़ा भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम तोड़ देती हैं।

रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के अशोधित अवशिष्टों और शहरों के हजारों टन अशोधित मल-मूत्र के कारण नदियां विषाक्त हो रही है। कारखानों से निकलने वाला टनों मलवा भी नदियों में झोंका जाता है। यह आत्मघाती कदम है।

कभी लोग नदियों के साथ सामंजस्य से रहा करते थे। जब मनुष्य असभ्य था, तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थीं। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है, तब नदियां मलिन और विषाक्त हो गयीं हैं। उन दिनों नदियों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता थी, परन्तु बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदियां अपनी यह क्षमता खोती जा रही है।

रणभेरी का समय

जल प्रदूषण के विरुद्ध रण-भेरी का समय आ गया है। हमने तुरन्त कदम न उठाये तो हमारी पवित्र नदियों का पानी इस कदर गंदा हो जायेगा कि उन्हें साफ करना असम्भव हो जायेगा। हमारा खाद्य उत्पादन घट जायेगा। व्यापक रोग फैल जायेंगे और लोग बेमौत मारे जायेंगे। अगर नहीं चेते तो इस गलती को सुधारने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। हमें नदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को बंद करना होगा।

हमें नदियों में फिर से प्राण-प्रतिष्ठा करनी होगी। रसायनों के बेरोक-टोक प्रयोग को रोकना होगा। कारखानों के अवशिष्ट, रासायनिक खाद, घातक रसायन, कीटनाशक और औद्योगिक कचरे से नदियों को बचाना होगा। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे मानव जाति का पाला पहले कभी नहीं पड़ा। लेकिन इस विकट चुनौती का दृढ़ता से सामना करना ही होगा। उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने अवशिष्टों को शोधित करने के बाद ही नदी में डालें।

पानी की हर बूंद एक चमत्कार है। पानी पर हमारा अधिकार नहीं। वह वरदान है। पानी प्राणाधार है। हमें पूरी निष्ठा के साथ उसकी रक्षा करनी चाहिये। हमारा अस्तित्व पानी पर निर्भर है। क्या हम उसे ही नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे? रहीम ने कहा ही है-रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। ■

पर्यावरण जागरूकता रैली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (पश्चिमी उ.प्र.) मेरठ महानगर में 5 जून, 2010 लगभग 100 साईकिलों के द्वारा 200 की संख्या में रैली के द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया। 5 जून सुबह 10.30 बजे यह रैली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न स्थानों बच्चा पार्क, बेगम पुल, पी.एल. शर्मा रोड, कमिश्नरी चौपला होते हुए जैसे ही मेरठ महानगर के सबसे बड़ी संख्या के डिग्री कॉलेज मेरठ कॉलेज पहुंची वहां पर उपस्थित सैकड़ों छात्रों ने रैली का फूल बिखेर स्वागत किया। इसके पश्चात् रैली साकेत चौपला, जेल चुंगी होते हुए सूरजकुंड पहुंची व्यापारियों ने अपने अध्यक्ष, मंत्रियों के साथ रैली का जोरदार स्वागत किया। रैली का समापन परिषद् कार्यालय पर हुआ।

विद्यार्थी परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने झण्डी दिखाकर रवाना किया।

रैली में उपस्थित टी.एस.वी.पी. प्रान्त प्रमुख अंकुर राणा, सह प्रमुख साहिल शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित राणा, वरुण शर्मा, मोहित तोमर, गोल्डी भारद्वाज, हिमांशु गुप्ता आदि कार्यकर्ता रहे।

कथा-साहित्य

यह धरती कितना देती है।

■ आशुतोष

बरसात के आखिरी दिन थे। कमरे के बाहर कड़ी धूप थी और अंदर उमस आलस से भरकर मैंने एक लम्बी जमुहाई ली। कमरे के कोने में मक्खी जैसा एक क्षुद्र जीव मुझे मंडराता हुआ दिखाई दिया जिसे मैंने वहीं बैठे-बैठे उड़ाने की कोशिश की।

मेरे हाथ हिलाने, अखबार हिलाने और मेज पर हाथ मारकर आवाज करने पर वह एक जगह से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता था। मैं देख रहा था कि वह मेरी हर गतिविधि पर नजर रखे था किन्तु गर्मी के कारण मेरी ही तरह कमरे के बाहर निकलने को तैयार नहीं था। कुछ देर के प्रयत्न के बाद मैंने उसे कमरे से भगाने का इरादा छोड़ दिया और बासी अखबार की रेखाओं पर नजर गड़ा दी।

जैसे रेल में तीस रूपये ज्यादा देकर आदमी मान लगता है कि पूर रास्ते के लिए उसने यह बर्थ खरीद ली है। किसी यात्री के बैठने का उपक्रम करने ही भड़क उठता है और आरक्षण का हवाला देता है, दूसरे यात्री का आदमीपन उसे ललकारता है और वह पहले यात्री के सारे तर्कों को नजर अंदाज कर देता। पहला यात्री जोर-जोर से बोलता रहता है और इस नाटक का दर्शक रूप में आनंद ले रहे यात्रियों को अपने संघर्ष में शामिल करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे वास्तविकता का अनुभव होता है। जब वह देखता है कि दूसरा यात्री इत्मीनान से सीट पर बैठकर पड़ोसी के अखबार में छपे अभिनेत्री के फोटो पर अपनी निगाहें टिका चुका है। यह 'रिअलाइजेशन' ही उसे प्रेरित करता है कि वह नये यात्री के सह अस्तित्व को स्वीकार कर ले।

मेरे कमरे में घुस आये इस क्षुद्र प्राणी के साथ हुआ मेरा संघर्ष भी मेरे इस खालिस आदमीपन का ही नतीजा था। वह मेरी कमजोरी को समझ चुका था और भांप गया था कि मैंने भी उसके साथ सह अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। और इसका सीधा अर्थ था कि अब उसे मुझसे कोई खतरा नहीं था।

रेलयात्रा में वाक्युद्ध और सहअस्तित्व की स्वीकारोक्ति के बाद अगला दौर होता है वार्तालाप का जो प्रायः 'आप कहां जायेंगे' से प्रारंभ होकर देश-दुनिया की राजनीति पर पहुंचता है और अंतिम पड़ाव आने पर ही रूकता है। ठीक उसी अंदाज में वह प्राणी कमरे के कोने में उड़ा और मेज पर मेरे बिल्कुल सामने आ बैठा। मैंनें उसे गौर से देखा। वह मक्खी न होकर बुढ़ी चींटी थी जिसके पर निकल आये थे। उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां थी वह जिससे जाहिर था कि वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में थी।

मुझे अपनी ओर देखते देख वह धीमे से मुस्कुराई और बोली 'हैलो'। क्या है? मैं गुर्राया।

मेरे अंदर का आदमीपन फिर जाग उठा था और मुझे सचेत कर रहा था कि एक बुढ़ी चींटी से बात करने में मेरी अपनी ही तौहीन है। मैं तुम से बात करना चाहती हूँ। चींटी बोली।

मेरे पास समय नहीं है। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा। यह पुराना अखबार है और पिछले तीन दिन में दस से ज्यादा बार तुम पलट चुके हो।

सच तो यह है कि तुम्हारे पास फिलहाल कोई काम नहीं है और अपनी बोरियत दूर करने के लिए तुमने इसे एक बार फिर उठा लिया है।

ऐसा लगा जैसे चींटी ने मेरी चोरी पकड़ ली हो।

मैंने चींटी को घूरा। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। मेरी और देखकर उसने अपने पंख हिलाये।

ठीक है। बोलो! क्या कहना चाहती हो?

आप मुझे कमरे से क्यों भगाना चाहते थे?

क्योंकि यह मेरा कमरा है। इस कमरे में मुझे किसी और की उपस्थिति स्वीकार नहीं है। एक चींटी की भी नहीं।

पर क्यों? किस अधिकार से तुम मुझे भगाना चाहते हो?

क्योंकि मैं इसका भाड़ा देता हूं।

यह भाड़ा देकर आपने अपने रहने का अधिकार खरीदा है या औरों को न रहने देने का? मैं इस कमरे में तुमसे पहले से रह रही हूं।

ठीक है! पर अब यह कमरा मेरा है और तुम्हें कहीं और जगह ढूंढनी चाहिए। जो कमरे का किराया देगा, वही रहेगा। और कोई नहीं। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मालिक से बात करो। मुझसे नहीं। तुम्हें यह कमरा छोड़ना होगा।

मकान मालिक को क्या हक है मुझे निकलने का? मैं यह कमरा नहीं छोड़ूंगी। चींटी अब बहस पर उतर आई थी और मैं अपना धैर्य खोता जा रहा था। झल्लाये हुए स्वर में मैंने कहा- क्योंकि मकान मालिक ने जमीन खरीदी है। क्योंकि मकान मालिक ने मकान बनया है, इसलिए इमसें वहीं रह सकता है जिसे मकान मालिक चाहे।

मकान मालिक ने यह जमीन किससे खरीदी? चींटी ने प्रश्न किया।

अपने क्रोध पर काबू करते हुए मैंने कहा-जमीन के मालिक से। और उसको यह जमीन अपने पिता से मिली जिसके दादा के दादा को राजा ने ईनाम में दी थी। अब और कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चुटकी में लेकर मसल दूं इससे पहले यह कमरा छोड़ दो।

राजा कौन होता है किसी को जमीन ईनाम में देने वाला? चींटी ने मेरे क्रोध को नजर अंदाज करते हुए नया सवाल दाग दिया।

और क्या तू है इस जमीन की मालिक? गुस्से से चीखते हुए मैंने कहा।

मैंने तय कर लिया था कि अब अगर इसने एक भी सवाल किया तो मैं उसे मसल डालूंगा। नहीं। चींटी ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया। पहली बार चींटी ने सवाल करने के बजाय 'नहीं' कहा था। मैं समझ गया कि मेरे गुस्से के आगे उसके हथियार डाल दिये हैं और अब वह मेरा कमरा छोड़ देगी। विजय के दर्प के साथ मैंने अपने स्वर को नीचे लाते हुए कहा-जब तुम मानती हो कि तुम यहां की मालिक नहीं हो तो जो इसका मालिक है उसके अधिकार का सम्मान करो और कमरा खाली कर दो।

अपने शब्दों में दृढ़ता लाते हुए वह बोली-मैंने केवल यह स्वीकार किया है कि मैं मालिक नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने इस जमीन पर तुम्हारे मालिक का या उस राजा का अधिकार स्वीकार कर लिया है। चींटी की बातें अब रहस्यमय होती जा रही थीं। मैंने कहा-जब तुम मालिक नहीं हो, मकान मालिक और राजा भी मालिक नहीं है तो आखिर मालिक है कौन?

हवा का मालिक कौन है? चींटी ने प्रतिप्रश्न किया।

मैंने प्रश्न न समझ पाने की मुद्रा में सर हिलाया।

अपने प्रश्न को स्पष्ट करते हुए वह बोली-जब हवा, पानी, नदी, पहाड़, झरने, सागर सब मुक्त हैं, इनका स्वामी कोई नहीं है तो धरती का स्वामी कोई कैसे हो सकता है? जब ये सब नहीं बिकते तो धरती कैसे बिक सकती है? कोई कैसे उसे खरीद सकता है? धरती के सौदे करने, ईनाम में देने का हक मनुष्य को किसने दिया? अब मैं निरूत्तर था। मैंने देखा कि अपनी बात कहते-कहते चींटी के झुर्रीदार चेहरे पर अलौकिक आभा व्याप्त हो गई थी।

वह बोली-तुमसे मैं तुम्हारी शब्दावली में ही एक सवाल करती हूं-यदि दो भाइयों के पास एक साझी सम्पत्ति है तो क्या कोई एक भाई अपने फायदे के लिए उसे बेच सकता है? बिना दूसरे भाई के पूछे किसी को दे सकता है?

नहीं! मैंने कहा-दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है कि वे उस साझी सम्पत्ति का मिलकर संरक्षण करें। उमसें वृद्धि करें। यदि कोई निर्णय करना हो तो दोनों की सहमति से ही हो। भाई बड़ा हो या छोटा-दोनों की जिम्मेदारी बराबर है और अधिकार भी। किसी को हक नहीं कि दूसरे के अधिकारों का हनन करें।

बिल्कुल ठीक। तुम्हारी हर बात मेरे इस कमरे में रहने के अधिकार का समर्थन करती है। वह कैसे? मैंने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा।

इस धरती पर केवल मनुष्य ही नहीं रहते हैं। लाखों प्रजातियां हैं जन्तुओं की, वनस्पतियों की। कीट-पतंगों का अपना एक सम्पूर्ण संसार है। यह धरती उन सबकी भी उतनी ही अपनी है जितनी कि तुम्हारे इस मकान मालिक की। मेरी भी उतनी है जितनी राजा की। मकान मालिक ने अपना बनाया घर तुम्हें बेचा है, पर इसी जमीन पर मेरा घर भी है जो मैंने तुम्हें नहीं बेचा है। मालिक न मैं हूं, न वह। जो धरती सबकी है उसका

शेष पृष्ठ 23 पर

9 जुलाई - विश्व विद्यार्थी दिवस

■ **गौरव शर्मा**, *राष्ट्रीय छात्रशक्ति प्रमुख*

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ लोगों के मानस में मैकाले व मार्क्स के आधार पर चलने की कल्पना थी। जो पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित होकर उन्हीं को अपना आदर्श मानने लगे तो कुछ समता को प्रस्थापित करने हेतु सतत आपसी संघर्ष के मॉडल को उपयुक्त मान रहे थे। जो रूस की क्रांति से प्रभावित था। कुछ लोग सोच रहे थे हमारे पूर्वजों ने देश के लिए संघर्ष किया है। इसलिए अब इस पर शासन करने का अधिकार हमारा है।

1947 से ही यह अनुभव आने लगा सचेत व सक्रिय छात्र समुदाय के बिना राष्ट्रीय नेतृत्व सत्ता की स्वाभाविक विकृतियों के चलते स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों से हट सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रवादी शिक्षाविद्, शिक्षक व शिक्षार्थियों ने मिलकर अभाविप की स्थापना की। 9 जुलाई 1949 को अभाविप प्रथम पंजीकृत छात्र संगठन बना। परिषद की स्थापना हो रही थी, उसी समय देश के संविधान की निर्मिती का प्रयास चल रहा था। अभाविप ने मांग रखी- देश का नाम भारत हो, वन्देमातरम् राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रभाषा हिन्दी हो। इसी मांग से अभाविप की दृष्टि व दिशा स्पष्ट हो गई। 1960 का दशक छात्र सक्रियता का दशक था। तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। परन्तु शैक्षिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में वैसी प्रगति नहीं हुई जिसकी अपेक्षा थी। जगह-जगह पर छात्र आन्दोलन हो रहे थे। परन्तु विद्यार्थी को मान्यता नहीं मिल रही थी। उसे कल का नागरिक कहा जाता था। अभाविप ने सर्वप्रथम 1971 में अपना मौलिक प्रतिपादन देश के सम्मुख रखा और कहा **'छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है'**। समान जीवन में इसकी भूमिका सहभोगी की नहीं सहभागी की है। उसी मांग और अभाविप के प्रयास के फलस्वरूप बाद में 18 वर्ष के युवा को मताधिकार प्राप्त हुआ।

1973 में गुजरात के मोरवी इंजीनियरिंग कालेज में फूड बिल की बढ़ोत्तरी के विरोध में आन्दोलन शुरू हुआ। जिसे अभाविप ने रोटी-रमखाण (रोटी के लिए लड़ाई) में बदल दिया। इसी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन ने गुजरात के राजमुकुटों को भुलुण्ठित कर दिया। 1975 में इसी आन्दोलन की लपटे बिहार तक पहुंची। जिस आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायणजी ने किया। और इसे पूरे भारत में व्याप्त अभाविप ने किया। इसी आन्दोलन से डरकर इंदिरा सरकार ने लोकतंत्र को सलाखों के पीछे धकेल दिया। देश में आपात्काल लगा देश में दूसरी आजादी की लड़ाई अभाविप के नेतृत्व में छात्र समुदाय ने लड़ी। जिसके परिणामस्वरूप मौन बना जनमत मुखर हो उठा। वोट की ताकत को नई धार दी। और दानवी तानाशाही को पाश-पाश कर दिया।

मुद्दा बंगलादेशी घुसपैठ हो, असम हो, तीन बीघा जमीन का हो या शिक्षा के व्यापारीकरण का हो, नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष हो या परिसर संस्कृति की स्थापना का विषय हो अभाविप ने इन सब आन्दोलनों को जीवंत रूप से लड़ा है। और अभाविप के कार्यकर्ता में इसका प्रतिबिम्ब समाज ने देखा है। भारत का सही इतिहास, उसकी संस्कृति उसकी मान्यताएं, शाश्वत शुद्ध सिद्धांतों को जीवंत रखने का आग्रह व कालबाह्य चीजों को छोड़ने की दृढ़ता अभाविप में दिखाई देती है। इसी कारण विद्यार्थी समुदाय का जुड़ाव मौलिक, रचनात्मक, आन्दोलनात्मक स्वभाव के कारण अभाविप से हुआ है। जो उत्तरोत्तर रूप से बढ़ता जा रहा है।

जब महाविद्यालयों में नये छात्र-छात्राओं से रैगिंग होती थी। तब अभाविप नवागन्तुक छात्र अभिनन्दन के कार्यक्रम आयोजित करती थी। और इसी के कार्यकर्ता छात्र-छात्राओं की सहायता को तत्पर रहते थे। इसी का परिणाम है कि आज परिसर में सभी छात्र संगठन नवागन्तुक छात्रों का स्वागत करते हैं। प्रवेश सहायता केन्द्र लगाते हैं पहले जातियों के द्वारा मेधावी छात्रों के अभिनन्दन किए जाते थे। अभाविप ने पहली बार क्षेत्रीय व जातीय भावना से ऊपर उठकर मेधावी छात्रों के अभिनन्दन समारोह आयोजित करना शुरू किया।

धारा को चीर कर चलने का साहस अभाविप का विशिष्ट गुण व अभाविप के कार्यकर्ता की मौलिक पहचान है। इसी वैशिष्ट्य ने अभाविप को दूसरे छात्र संगठनों से अलग खड़ा किया। अभाविप ने वन्देमातरम् के नारे को कार्य रूप में परीणित किया है। एवं भारत माता की जय को प्रत्यक्ष सक्रीयता में बदला है। छात्र को जाति, भाषा, धर्म, प्रान्त, क्षेत्र से ऊपर उठाकर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया है। छात्र-छात्राओं को देश के लिए कुछ करने के अनगिनत अवसर उपलब्ध करवायें हैं। इस कारण आम छात्र विद्यार्थी परिषद् से जुड़ाव महसूस करता है। **'9 जुलाई'** को अभाविप स्थापना दिवस के रूप में मनाती रही परन्तु आज देश का आम विद्यार्थी इसे विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता है।

विद्यार्थी दिवस यह अवसर परिसरों में नये विद्यार्थियों के स्वागत का अवसर भी है। नये शैक्षिक वर्ष हेतु नए संकल्प धारण करने का भी।

विद्यार्थियों के एक छोटे समूह से शुरू हुआ छात्र संगठन आज पूरे भारत में 3060 स्थानों तक पहुंच गया है। जिससे सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष 17, 15, 820 थी।

आज विद्यार्थी दिवस पूरे देश में 1760 स्थानों पर 3 लाख 85 हजार 870 विद्यार्थियों द्वारा मनाया जाता है।

यह अवसर है नये स्वप्न देखने व उन्हें कार्यरूप में परीणित करने का जो हम कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा व प्रयत्नों की परिसीमा से पूरे होंगे।

यह दिवस जो अभाविप के ज्ञान-शील-एकता के त्रिसंकल्प से स्थापना दिवस से आज आम विद्यार्थी का दिवस बन गया है। यह इससे एक कदम आगे बढ़कर जनाकांक्षा व जनविश्वास का दिवस बने। ■

नक्सल हमलों के विरोध में प्रदर्शन

अभाविप के द्वारा नक्सल हिंसा के विरोध में 4 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। दंतेवाड़ा हत्याकांड, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, आदि घटनाओं के विरोध में छात्र पूरे देश में अभाविप के नेतृत्व में एकत्र आये। और नक्सली हिंसा के विरोध में स्थान-स्थान पर ज्ञापन, धरना, पुतला दहन, मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन शहीदों को श्रद्धांजलि, विरोध मार्च आदि कार्यक्रम हुए। प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण निम्न हैं-

पंजाब में 9 स्थानों पर कार्यक्रम हुए। संख्या 670 रही। कार्यक्रम में शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि, ज्ञापन, पुतलादहन के कार्यक्रम हुए।

हरियाणा में 11 स्थानों पर कार्यक्रम हुए। रैली, पुतलादहन, शोक सभा, हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव आदि में कार्यक्रम हुए। संख्या 698 रही।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नक्सल हिंसा के विरोध में 47 स्थानों पर प्रदर्शन हुए जिसमें 1647 कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन एवं प्रदर्शन किए गए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सल हिंसा के विरोध में 8 स्थानों पर धरना, ज्ञापन आदि कार्यक्रम हुए। जिसमें संख्या 155 रही।

मध्य भारत प्रान्त में नक्सल हिंसा के विरोध में कुल 58 स्थानों पर 58 कार्यक्रम हुए जिसमें 1954 संख्या रही इन स्थानों पर धरना, पुतला दहन, ज्ञापन के स्वरूप में विरोध प्रदर्शन हुआ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्टफैकल्टी पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रात: 11 बजे अभाविप के प्रदेश भर के कार्यकर्ता आर्टफैकल्टी पर एकत्र हुए कार्यकर्ता रैली के रूप में भारत माता की जय, वन्देमातरम् का जयघोष करते हुए लॉ फैकल्टी होते हुए। क्रांति चौक पर पहुंचे। वहां पर 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। उसके पश्चात् सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में विवेकानन्द की प्रतिमा पर पहुंचे। जहां पर छात्रनेताओं ने छात्र सभा को सम्बोधित किया।

इसी क्रम में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल, बिहार, राजस्थान आदि प्रान्तों में भी व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों व आम जन ने बढ़चढ़कर भाग लिया। ■

अभाविप : स्थापना की पृष्ठभूमि

■ डॉ. प्रदीप राव

भारतीय स्वाधीनता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। बिना किसी संशोधन के 15 जुलाई को कामनसभा ने और 16 जुलाई को लार्ड सभा ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया। 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हुए और घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 से भारत के दो टुकड़े हो जायेंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्वमान होंगे। यह घोषणा एक दीर्घकालीन स्वाधीनता संग्राम का परिणाम थी। तथापि इस घोषणा के समय खण्डित भारत जश्न मनाने की जगह अपनों की लाशें गिन रहा था। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ पंजाब में छः लाख लोग मारे गये, एक करोड़ चालीस लाख शरणार्थी बना दिये गये, एक लाख युवतियों का अपहरण कर उन्हें बलात् धर्म परिवर्तन कर गृहिणी बना दिया गया। क्योंकि भारत विभाजन के पीछे कट्टरवादी इस्लामी सोच महत्त्वपूर्ण कारण था। सैकड़ों सालों तक चलने वाले बाहरी आक्रमणों एवं आन्तरिक पाँथिक संघर्षों के बावजूद अखण्ड भारत का बँटवारा अन्ततः हिन्दू-मुस्लिम दो विचारधाराओं के आधार पर परिभाषित 'द्विराष्ट्रवाद' के सिद्धान्त पर ही हो सका।

वस्तुतः आजादी के समय भारत में मुस्लिम समाज के लिए राष्ट्रवाद और धर्म दो बिलकुल अगल सत्ताएँ एवं विषय था जब कि हिन्दू के लिए धर्म और राष्ट्र एकाकार था। परिणामतः परतन्त्र भारत में मुस्लिम लीग ने अपने पूरे राजनीतिक संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष आन्दोलन नहीं छेड़ा। शुरू से ही मुस्लिम लीग के लिए उसकी विरोधी अंग्रेजी सरकार न होकर कांग्रेस एवं कथित हिन्दूराज था। वास्तव में मुसलमानों के लिए इस्लाम, तलवार और विजित क्षेत्र तीनों एक रूप है। अन्ततः मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ऐलान कर दिया कि किसी मुसलमान के लिए चाहे वह किसी देश का हो, यह सम्भव नहीं कि वह दूसरे मुसलमान के विरुद्ध खड़ा हो सके। 1. मोहम्मद अली जिन्ना ने 7 अप्रैल 1946 को दिल्ली के सम्मेलन में घोषणा की- हम दस करोड़ का एक राष्ट्र हैं। इससे भी अधिक हम अपनी अलग सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य, कला, नाम, मूल्यबोध के साथ, कानून, नैतिक संहिता, रीतियाँ, तिथियाँ, इतिहास, परम्पराएँ, दृष्टि एवं महत्त्वाकांक्षाओं में, संक्षेप में, हमारे पास जीवन के प्रति व जीवन का एक अलग दृष्टिकोण है।

2. वस्तुतः इसकी शुरुआत तभी हो गयी थी जब 1908 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मण्डल दिये जाने की संस्तुति करते हुए भारत की ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 'भारतीय मुसलमान मात्र एक धार्मिक संरचना से अधिक है। वास्तव में वे पूरी तरह एक अलग सम्प्रदाय का निर्माण करते हैं जो विवाह, भोजन, परम्पराओं में अलग है।' अन्ततः मुस्लिम नेतृत्व ने यह कहते हुए कि हिन्दू-मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं, दोनों कभी भी एक साथ रह ही नहीं सकते, भारत विभाजन के प्रस्ताव पर मुहर लगवा ली। यह विभाजन शांतिपूर्ण भी हो सकता था, किन्तु जैसा कि उपर लिखा जा चुका है दुनिया के भीषणतम् नरसंहारों में एक बड़े नरसंहार की पटकथा के साथ भारत विभाजन का अध्याय लिखा गया। ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी नरसंहार के साथ द्विराष्ट्रवाद् सिद्धान्त पर खण्डित भारत आजाद हुआ। स्वाभाविक था कि इस्लाम के अनुयायी अपना हिस्सा ले चुके थे अतः शेष भारत हिन्दुओं का था। इस्लाम के धार्मिक आधार पर बने पाकिस्तान के जन्म से भारत की हिन्दूराष्ट्र की अवधारणा स्वतः सिद्ध हो गयी। इस बँटवारे के बाद हिन्दू-मुस्लिम आधार पर आबादी का पूर्णतः स्थानान्तरण हो जाना चाहिए था। किन्तु कतिपय भारतीय नेताओं के कारण यह सम्भव न हो सका और भारत एक बड़ी गलतीकर बैठा। 'द्विराष्ट्रवाद' सिद्धान्त पर बहस के दौरान अनेक भारतीय नेताओं ने हिन्दु-मुस्लिम एकता के सन्दर्भ में अपनी शंकाएँ व्यक्त की थी। लाला लाजपत राय ने बंगाल के कांग्रेस नेता सी.आर. दास को लिखे पत्र में कहा कि- 'मैने अपना छः महीने से अधिक समय मुस्लिम इतिहास व कानून पढ़ने में व्यतीत किया है और मेरा निष्कर्ष है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता व्यावहारिक एवं सम्भव दोनों नहीं है। इस्लाम में ही इस सम्भावना पर प्रतिबन्ध है। क्या कोई मुसलमान कुरान को नकार सकता है? मैं केवल आशा ही कर सकता हूँ कि मेरी कुरान के बारे में समझ गलत है और

यदि ऐसा है तो मैं बहुत आश्वस्त हो जाऊँगा। मैं ईमानदारी के साथ व निष्कपट रूप से हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता व सार्थकता का पक्षधर हूँ। मैं मुस्लिम नेताओं की ईमानदारी पर भरोसा करने पर भी तैयार हूँ परन्तु कुरान व हदीस के आदेशों का क्या किया जा सकता है?"

1924 में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर लिखा है कि- 'कोई मुसलमान अपनी देशभक्ति केवल एक देश के प्रति सीमित नहीं कर सकता...। मैंने कई मुसलमानों से स्पष्ट शब्दों में पूछा कि यदि कोई मुस्लिम शक्ति भारत पर आक्रमण करे तो क्या आप हिन्दू पड़ोसियों के साथ अपने देश को बचाने के लिए खड़े होंगे? इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला।'

लगभग यही बात अपनी पुस्तक 'बियाण्ड बिलीव' में नायपाल लिखते हैं। उन्होंने लिखा है- इस्लाम सिर्फ अन्तरात्मा या व्यक्तिगत विश्वास का सरल विषय नहीं है। यह साम्राज्य की माँग करता है। एक परिवर्तित व्यक्ति (इस्लाम स्वीकार कर लेने वाले) की विश्वदृष्टि बदल जाती है। उसके पवित्र स्थान अरब में है, उसकी पवित्र भाषा अरबी है। उसके इतिहास की अवधारणा बदल जाती है। वह स्वयं का बहिष्कार कर देता है। एक परिवर्तित व्यक्ति को हर उस चीज से मुँह मोड़ना पड़ता है जो उसकी अपनी है। परिवर्तित इस्लाम में नकारवाद और उन्माद का तत्त्व रहता है, ये कभी भी उबाल पर रखे जा सकते हैं।'

वस्तुत: ब्रिटिश भारत में मुस्लिम वर्ग के पास न तो राष्ट्रवाद सी कोई अवधारणा कभी पनपी और न ही इसे अल्पसंख्यक होने का कभी कोई बोध हुआ, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व सदियों से मूल सत्ता उसी के पास थी। मुस्लिम मजहब, समाज एवं राजनीति में भी मुस्लिम अल्पसंख्यक ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। उसकी समग्र संरचना इसी आधार पर है कि इस्लाम ही स्थितियों का संचालक है, नियन्ता है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज कैसे किसी बहुसंख्यक समाज में लचीलेपन एवं सहयोग के साथ रह सकता है इस सन्दर्भ में न तो कोई स्पष्ट निर्देश है न इसके ऐतिहासिक उदाहरण है। कुरान में किसी हदीस या किसी मुस्लिम न्यायविद या मौलवी ने इस पर कुछ नहीं कहा कि जब किसी देश में शासन मुसलमानों का न हो तक कैसे रहा जाय। इस्लाम की उत्पत्ति मूलत: कबीलाई संगठन के रूप में हुई, तलवार से वह फैला और अपने गहरे अन्तर्गुम्फन, एकनिष्ठ कट्टरता और निर्विवाद संरचना के बल पर बना रहा। उसमें किसी तरह के समायोजन या मध्यमार्ग की सम्भावना नहीं थी। इस्लाम का इतिहास दिखाता है कि धर्म और जीवन पद्धति में वह केवल तभी प्रभावी और उन्नत हो सकता है जब इस धर्म के पास राजनीतिक शक्ति एवं सत्ता हो।[2] इस्लाम के इस स्वरूप को बहुत पीछे न भी जाया जाय तो 1883 में गठित मोहम्मडन पोलिटिकल एसोसियेशन के सचिव सैयद अहमद से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में देश विभाजन तक की लगभग साढ़े छ: दशक के मुस्लिम आन्दोलन एवं उनकी विचारधारा पर नजर दौड़ाई जाय तो यह बात बहुत साफ हो चुकी थी कि मुस्लिम समाज हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकता। यह बात स्वतंत्रता आन्दोलन में जुटे लगभग सभी महत्त्वपूर्ण भारतीय नेताओं के समझ में आ चुकी थी चाहे वह वल्लभभाई पटेल हों या भीमराव अम्बेडकर। किन्तु एक तीसरी वैचारिक ताकत समाजवाद एवं साम्यवाद के रूप में भारत में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इन समाजवादियों एवं साम्यवादियों को मुस्लिम लीग का इस्लामी राष्ट्र तो समझ में आ रहा था, वे उसके समर्थन में भी थे किन्तु हिन्दू राष्ट्र न बनने देने के षड्यंत्र में वे पूरी शक्ति लगाये हुए थे। वे भारत के दो टुकड़े करने मात्र से सन्तुष्ट नहीं थे। उल्लेखनीय है कि सी.पी.आई. ने कैबिनेट मिशन के सामने भारत को 17 भाषाई और सांस्कृतिक इकाईयों में बाँट देने की माँग की थी। और दुर्भाग्यवश जवाहरलाल नेहरू इन समाजवादियों एवं साम्यवादियों के हथियार बन गये। महात्मा गाँधी की कमजोरी जवाहरलाल नेहरू ने खण्डित भारत को 'धर्मनिरपेक्ष भारत' घोषित करने में सफलता प्राप्त की और समाजवादी तथा साम्यवादी अपने षड्यंत्र में सफल रहे।

यह महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी नेताओं ने मुसलमानों को अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए देश के बड़े हिस्से को देना तो स्वीकार कर लिया

किन्तु विभाजित भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने से इन्कार किया। मुसलमानों को इस तरह दोनों चीजें मिली। अपने अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान और धर्मनिरपेक्ष एवं विशेष अधिकारों वाला हिन्दुस्तान भी।

स्वतंत्र भारत की सत्ता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने संभाली। आजादी के बाद का कालखण्ड अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। देश के सामने एक यक्ष प्रश्न था कि आजाद भारत का पुनर्निर्माण कैसा होगा, किस सोच से होगा। हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द समाप्त हो चुका था। इस्लामी राज्य का स्वप्न देखने वालों को पूर्वी-पश्चिमी पाकिस्तान दिया जा चुका था। अत: सामान्यतया यह माना जा रहा था था कि भारत अपनी मूल सनातन संस्कृति की आधारशिला पर खड़ा होगा और दुनिया में भारत को श्रीराम-कृष्ण के देश के रूप में पहचान मिलेगी। एक राष्ट्र-एक जन के सिद्धान्त पर देश फले-फूलेगा। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही महात्मा गाँधी राम-राज्य की परिकल्पना साकार होने का स्वप्न सँजोये बैठे थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द, महामना मदनमोहन मालवीय, बालगंगाधर तिलक, वीर दामोदर सावरकर, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जैसे भारतीय मनीषियों ने स्वतन्त्र भारत के पुनर्निर्माण का जो खाका खींचा था उसे पूरा करने हेतु स्वतन्त्र भारत की समकालीन पीढ़ी तत्पर थी। भारतीय संस्कृति की विरासत पर भारत के पुननिर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन्नद्ध था।

व्यक्ति निर्माण से सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में स्वतत्र हुए भारत के युवाओं को खड़ा करने में राष्ट्रवादी संगठन लगे हुए थे। भारत का राष्ट्रवादी समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। भारत आजाद होकर भी अपना सब कुछ गंवा चुका था। बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की साम्प्रदायिक हिंसा, हिन्दू नेताओं की मूकदर्शक स्थिति और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त पर मुस्लिम भारत (पाकिस्तान) अलग होने के बाद भी आबादी का पूर्ण स्थानान्तरण न होने देना, भारत की सनातन संस्कृति को उपहास का हिस्सा बनाये रखना तथा आजादी के बाद भी ब्रिटिश विरासत को बनाये रखने की साम्यवादी-समाजवादी प्रयास की सफलता से अभी भारत उबर भी नहीं पाया था कि 'महात्मा गाँधी की हत्या' हो गई। साम्यवादी-समाजवादी गठजोड़ के नेता जवाहरलाल नेहरू को एक बहाना मिल गया और झूठे आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा भारतीय संस्कृति की आधारशिला पर भारत के पुनर्निर्माण के समर्थक जेल में डाल दिए गये। ये परिस्थितयाँ किसी भी राष्ट्रवादी युवा मन को झकझोर देने वाली थी और लगता है कि अभी-अभी स्वतंत्र हुए भारत की इन्ही परिस्थितियों के गर्भ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् जैसे छात्र संगठन को जन्म दे दिया।

१. टाइम्स आफ इण्डिया, १८ अप्रैल १९२४
२. पीरजादा, फाउण्डेशन ऑफ पाकिस्तान, खण्ड-२, पृष्ठ-५०५
३. द्रष्टव्य, प्रियंवाद, देश विभाजन की अन्तकथा, पृष्ठ-४०६
४. वही, पृष्ठ-४०९
५. बी. एल. नायपाल, विमाण्ड विलीव, पृष्ठ-१

पृष्ठ 18 का शेष

मालिक सिर्फ मनुष्य कैसे? कब स्वीकार करेगा मनुष्य इस सत्य को।

यह धरती सबकी जरूरतें पूरी करती है। हम इससे लेते रहते हैं पर इसे लौटाते क्या हैं? हमारे पूर्वजों ने इसे उर्वरा बनाया, जीवन दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी इस जीवन यात्रा में इसे और अधिक सुन्दर बनाकर जायें ताकि आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकें। बादल का टुकड़ा जैसे इस धरती को हरा-भरा बनाने के लिए अपने अस्तित्व को पूरी तरह विलीन कर देता है, वैसे ही हमें समाप्त हो जाना है। सभी कामनाओं से दूर। सभी वासनाओं से दूर।

तलवारों की दम पर, खून की नदियां बहाकर स्थापित किए गए राज्यों के उत्थान-पतन का इतिहास तो बार-बार लिखा गया है। धरती का जीवन शक्ति देने वाले, उर्वर बनने वाले, केंचुओं, कृमियों की लाखों प्रजातियों का इतिहास क्या कभी लिखा जायेगा?

तुम्हारे पास आग उगलने वाले हथियार हैं, मुझे या मुझ जैसे जीवधारियों को चुटकी में मसल देने की ताकत है, क्या इससे यह धरती तुम्हारी हो जायेगी? क्या तुम्हारे पास मेरी बातों को नकारने का नैतिक आधार है? यदि है तो जवाब दो।

मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे पास उसके सवालों का जवाब नहीं है। ■

सामाजिक विभेद का पर्याय रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट–*सुनील बंसल*

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् जयपुर महानगर के द्वारा 29 अप्रैल, 2010 को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभो महाविद्यालय में 'रंगनाथ मिश्रा आयोग पर कार्यशाला' आयोजित की गयी।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री सुनील बंसल, मुख्य वक्ता श्री मदन दिलावर पूर्व मंत्री एवं अध्यक्षता श्री राजीव सक्सेना पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने की।

कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

मुख्य अतिथि श्री सुनील बंसल ने सम्बोधित करते हुए कहा कि परिषद् हमेशा से अस्पृश्यता की विरोधी रही है और सदैव कार्यक्रमों से समाज में समरसता का भाव जगाने के लिए कार्य करती रहती है।

श्री बंसल ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट धर्मान्तरण को बढ़ावा देने वाली है और यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार की तुष्टीकरण की मानसिकता का परिचय है जिसका विरोध होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार उन्हीं जातियों को अनुसूचित जाती में आरक्षण का प्रावधान है जो हिन्दू धर्म में है, यह रिपोर्ट ही असवैधानिक है।

राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री सुनील बंसल

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री मदन दिलावर पूर्व मंत्री एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव सैक्सेना ने की। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक सुनील खटीक ने किया, कार्यक्रम में 150 छात्र प्रतिनिधि उपस्थित थे। ■

अमुवि में लागू हो आरक्षण–*कृष्ण गोपाल*

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब तक आरक्षण नीति लागू नहीं की गई है। गत् 60 वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन पिछड़े और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। इसका लाभ हजारों छात्रों एवं शिक्षकों को नहीं मिला है। आजादी के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसका चरित्र अल्पसंख्यक है या सामान्य? उक्त विचार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के असम क्षेत्र प्रचारक श्री कृष्ण गोपाल जी ने व्यक्त किए।

पटना के बीआईए हॉल में सात जून को आयोजित इस संगोष्ठी में श्री गोपाल जी ने कहा कि अमुवि में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से आजादी से लेकर अब तक इस श्रेणी के करीब 50 हजार छात्र वहां पढ़ने से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में कानून का पालन नहीं हो रहा है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि केन्द्र सरकार तुष्टीकरण की नीति चलाकर राष्ट्रीय सम्प्रभुता व सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुछ तथाकथित राजनेता राजनीतिक स्वार्थ के कारण यह सब कर रहे हैं। श्री गोपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में पिछड़े और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को आरक्षण मिले, इसके लिए वर्तमान राजनेताओं को पहल करनी होगी।

इससे पहले विषय प्रवेश करते हुए राष्ट्रीय मंत्री श्री रामाशंकर सिन्हा ने कहा कि अमुवि की शाखा किशनगंज में रखे जाने का विरोध होगा। क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री दिनेश कुमार ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति कर रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा व बिहार के लिए खतरनाक संकेत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक डा. शत्रुघ्न प्रसाद ने की। कार्यक्रम में संघ के उत्तर पूर्व क्षेत्र प्रचारक श्री स्वांत रंजन, प्रदेश संगठन मंत्री श्री निखिल रंजन, प्रदेश मंत्री राजेश सिन्हा, सह मंत्री आदित्य कुमार, भारतेन्दु मिश्रा व जिला संयोजक अमृतांशु शेखर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सीमांत पटेल व धन्यवाद ज्ञापन हिमांशु यादव ने किया।

■ संजीव कुमार

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के संक्षिप्त प्रस्ताव

देहरादून (27-30 मई 2010)

प्रस्ताव क्रमांक-1

शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए आवहान

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्य व सामाजिक उत्तरदायित्व समाप्त हो गये है। यह शिक्षा व्यवस्था मूल्यहीन एवं भौतिकतावादी पीढ़ी का निर्माण कर रही है। यह परिदृश्य राष्ट्र के स्वस्थ विकास को दुष्प्रभावित करने वाला है। उदारीकरण के बाद की सरकारी नीतियों के फलस्वरूप निजी शिक्षा संस्थान अचानक उत्कृष्टता केन्द्र के स्थान पर धनार्जन केन्द्र बन गये।

शिक्षा के त्वरित विकास में शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तों जैसे सहभागिता, समानता, सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशिता और सर्व सुलभता का गंभीर ह्रास हुआ है। स्वायतत्ता तथा गुणवत्ता के नाम पर कैपीटेशन शुल्क एवं असाध्य शुल्क संरचना आरंभ हुई है। AICTE, MCI, DCI जैसी अनेक नियामक संस्थायें, जिनसे शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने तथा व्यापारीकरण को रोकने की अपेक्षा है, अक्षम अथवा भ्रष्ट होकर व्यापारीकरण को रोकने में पूर्णतया असफल रही हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार में लिप्त MCI के अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई की गिरफ्तारी हमारी शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति का जीता-जागता उदाहरण है। ठीक इसी तरह के मामले में जांच ऐजेंसियों के द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. के अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने भी शिक्षा प्रणाली में इस तरह के भ्रष्ट लोगों के एकाधिकार को उजागर किया है।

संप्रग सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित 6 विधेयक प्रस्तुत किये हैं। शिक्षा सुधार के लिये सरकार की ऐसी पहल स्वागत योग्य तो है परन्तु विधेयकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि ये प्रयास वस्तुत: निजीकरण, शक्ति के केन्द्रीकरण तथा तुष्टीकरण को अधिकाधिक बढ़ावा देने वाले हैं। इनमें से कोई भी विधेयक शिक्षा के धरातलीय यथार्थ तथा वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ नही है। अभाविप यह अनुभव करती है कि ये प्रयास बदलते शैक्षिक एवं आर्थिक परिस्थिति में एकांगी दृष्टि से विचार का परिणाम हैं। आज समग्र दृष्टि से शिक्षा नीति बनाते हुए उस पर कानून बनाने की आवश्यकता है।

समाज एवं राष्ट्र के हित में शिक्षा के बाजारीकरण की इस भयावह स्थिति पर रोक लगाना तथा इसे सुलभ तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना इस काल की महती आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही हम सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् यह मानती है कि उच्च शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों के निर्माण में स्पष्टता एवं पारदर्शिता की आवश्यकता है। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों से यह मांग भी करती है कि निजी विश्वविद्यालयों तथा मानित विश्वविद्यालयों के कुकुरमुत्ते की तरह उगने की स्थिति को तत्काल रोकें। अभाविप इस तथ्य को स्वीकार करती है कि उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की सहभागिता अपरिहार्य है। किन्तु इन संस्थानों में मात्र धन कमाने के स्थान पर सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की मनोवृत्ति होनी चाहिए।

यदि सरकार द्वारा व्यापारीकरण को रोकने की दिशा में कदम उठाये जाते है, तो अभाविप उसका स्वागत करेगी साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि यदि शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिये तत्काल कदम नही उठाये गये तो इसके विरूद्ध अभाविप राष्ट्रव्यापी आन्दोलन प्रारंभ करेगी।

प्रस्ताव क्रमांक-2

देश की वर्तमान परिस्थिति

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में चन्द्रयान अभियान एवं अन्य प्रयोगों से देश के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं किन्तु उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार, बढ़ती मंहगाई, सामाजिक विषमताओं के राजनीतिकरण एवं विभाजन की द्योतक तुष्टिकरण की नीति वर्तमान परिदृश्य में निराशा उत्पन्न कर रही है। केन्द्रीय नेतृत्व की अक्षमताओं एवं अदूरदर्शी नीतियों के कारण पाक प्रायोजित आतंकी संगठनों का बढ़ता प्रभाव एवं नक्सलवाद का भयावह स्वरूप देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न-भिन्न कर रहा है जो कि चिन्ता का विषय है।

भारत की असीम क्षमता तथा विश्व का नेतृत्व करने की संभावना के बावजूद दृष्टिविहीन नेतृत्व के कारण केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एकता-अखण्डता को कायम रखने

एवं आम आदमी के जीवन में सामान्य आवश्कताओं की पूर्ति कर पाने में नाकाम रही है।

मुम्बई में हमलों के दोषी पाक आतंकी अजमल कसाब को न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए फांसी दिए जाने के निर्णय से भारत की न्यायप्रणाली की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में प्रतिपादित हुयी है। किन्तु कसाब की फांसी के निर्णय का हश्र अफजल गुरू की फांसी को लंबित रखने की कांग्रेसी तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा नही बनना चाहिऐ।

अभाविप की इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का मानना है कि विभिन्न छद्म नामों से शुरू हुआ नक्सली आन्दोलन आज देश में हजारों करोड़ रूपये की अवैध धन उगाही, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जवानों एवं सामान्य नागरिकों की निर्मम हत्याओं तथा देश के विकास स्त्रोतों को हिंसा के बल पर ध्वस्त करने वाले अपराधिओं के तांडव का प्रतीक बना है। नक्सलियों द्वारा अफजल गुरू को हीरो मानना एवं लश्करे तोयबा से नक्सलवादियों के सम्बन्ध की पुष्टि के उजागर होने के बाद नक्सलवाद का राष्ट्र विरोधी स्वरूप देश के समक्ष और अधिक स्पष्ट हुआ है।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिये गंभीर चुनौती मानते हुए नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लेने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह एवं केन्द्रीय गृहमंत्री पी.चिदबंरम द्वारा नक्सलवादियों के खिलाफ शुरू किये गए ग्रीन हंट ऑपरेशन को नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में उठाया गया प्रभावी कदम निरूपित करते हुए स्वागत करती है तथा केन्द्रीय गृहमंत्री से अपेक्षा करती है कि वे नक्सलियों के खात्मे के अपने संकल्प से पीछे नही हटते हुए इन प्रयासों को निर्बाध रूप से जारी रखें।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलवादियों द्वारा 76 सी.आर.पी.एफ. के जवानों की नृशंस हत्या पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथियों द्वारा जश्न मनाना घोर आपत्तिजनक तथा देशद्रोह का परिचायक है। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् इस कृत्य की कड़े शब्दों में निन्दा करती है तथा वहां की छात्र शक्ति का अभिनन्दन करती है जिसने ऐसे तत्वों का पुरजोर विरोध किया। जे.एन.यू. एवं देश के अन्य शिक्षा संस्थानों में छात्रों का नक्सलियों के विरोध में खड़े होना छात्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सकारात्मक भूमिका के सुखद संकेत हैं

मानवाधिकारवादियों द्वारा पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जवानों तथा सामान्य नागरिकों की हत्या पर चुप रहना तथा आतंकवाद के पर्याय नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाना इनके दोहरे चरित्र का परिचायक है। अभाविप ऐसे मानवाधिकारवादियों की घोर निन्दा करते हुए केन्द्र सरकार से मांग करती है कि पर्दे के पीछे रहकर नक्सलवादियों का समर्थन करने वाले तथाकथित मानवाधिकारवादी एवं छद्म राजनीतिज्ञों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा नक्सली आतंक के खिलाफ चल रहे अभियान को और गति देते हुए प्रभावी संयुक्त रणनीति बनायी जावें।

देश के गृहमंत्रालय द्वारा अफजल गुरू को फांसी के लिए दिल्ली स्थित राज्य सरकार को 29 बार पत्र लिखे जाने के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद एवं दिल्ली की कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा अफजल गुरू की फांसी को लेकर अपने बयानों में कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात करना संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के मर्यादाहीन आचरण को स्पष्ट करता है तथा लोगों को अपराधियों को बचाने के लिए दंगे करने को प्रेरित करता है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र तथा राज्य सरकार के इस कृत्यों की कड़े शब्दों में निन्दा करती है।

देश में आई.पी.एल. प्रकरण से खेलों में देशभक्ति एवं खेल भावना को गहरा आघात लगा है। वहीं इसमें व्यवसायी और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ और शरद पवार एवं प्रफुल्ल पटेल जैसे केन्द्रीय मंत्रियों की संलिप्तता दुर्भाग्यपूर्ण है।

मणिपुर राज्य बन्द के कारण वहां का जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का मानना है कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति के लिए केन्द्र सरकार की अदूरदर्शी नीति जिम्मेवार है। अभाविप केन्द्र सरकार से मांग करती है कि मणिपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रारम्भ कराते हुए अविलंब नागरिक आपूर्ति बहाल की जाये।

देश के अनेक भागों में गहराता भीषण जल संकट,

जीवन के बुनियादी आवश्यकता के प्रतीक शुद्व जल का उपलब्ध नही हो पाना एवं अनेक स्थानों पर पानी के लिये नागरिकों में परस्पर संघर्ष होना गंभीर चिन्तन का विषय है। अनियोजित एवं अनियमित विकास आधारित व्यवस्था के कारण ही पेड़ों की अंधाधुध कटाई एवं भूजल का शोषण बढ़ रहा है। अभाविप का मानना है कि विश्व स्तर पर प्राकृतिक संसाधनो का अंधाधुंध शोषण, ओजोन परत का क्षरण एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे जिन पर्यावरण सम्बन्धी प्रश्नों से आज समस्त मानव समाज उद्वेलित है उनके मूल में पाश्चात्य जगत एवं उनके अनुगामियों द्वारा अपनाये गये विकास के मापदण्ड और जीवन शैली है। यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् देश के युवकों का आह्वान करती है कि मानवता के सामने उत्पन्न पर्यावरण के प्रश्नों के समाधान हेतु समाज में जनजागरण करने तथा जल एवं जैव विविधता के संग्रहण एवं संवर्धन-संरक्षण हेतु आगे आकर अपने दायित्व का निर्वाहन करें।

प्रस्ताव क्रमांक:- 3

भारत में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण: एक घातक प्रवृति

विगत कुछ वर्षो से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के नाम पर संविधान की मूल भावना और प्रावधानों को तहस-नहस करने वाले अनेक प्रशासनिक प्रावधानों का प्रयास किया गया हैं। देश में पंथ निरपेक्षता की छदम् नीति के कारण धार्मिक विश्वास को राज्य द्वारा छात्रवृतियों, रोजगार, मकान आवंटन तथा बैंक ऋण पाने हेतु प्रमुख आधार माना गया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 दिसम्बर 2008 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में दिये गये वक्तव्य में कहा था कि राष्ट्रीय संसाधनों पर प्रथम अधिकार अल्पसंख्यकों का है। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के लिए बनायी गई समिति की रिपोर्ट, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है, में तोड़-मरोड़ कर पेश किये गये आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को सापेक्षिक दृष्टि से पिछड़ा दिखाया गया है। इसको आधार बनाकर मुसलमानों के उत्थान के नाम पर सभी प्रशासनिक मानकों के उलट धार्मिक आधार पर विभेद करने वाले उपायों को न्यायोचित ठहराने का काम किया गया है। उक्त रिपोर्ट के अनुवर्तन स्वरूप आयी धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को जिसे रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, में मुस्लिमों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसायें शैक्षिक प्रवेश हेतु एवं सभी सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के लिये की गई हैं। यह रिपोर्ट मुस्लिमों एवं ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा तथा सम्बन्धित लाभों को देने की भी वकालत करती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का मानना है कि ये विभेदात्मक संस्तुतियां एवं उपाय न केवल साम्प्रादायिक अपितु पंथ निरपेक्षता की मूल भावना के विरूद्ध है, बल्कि ये उपाय अपने एकमात्र उद्देश्य अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुख्यत: मुस्लिम तुष्टीकरण के षड्यंत्र हैं जिससे इस समुदाय के वोट प्राप्त किये जा सके।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई घोर तुष्टीकरण की प्रवृति का कई राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के एक निर्णय के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), जो कि 1940 के दशक में पाकिस्तान आंदोलन का प्रमुख वैचारिक केन्द्र रहा है, देश में पांच मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है। अ.भा. वि.प. की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् अनुभव करती है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केन्द्र देश भर में स्थापित करने का निर्णय प्रतिगामी एवं धूर्ततापूर्ण कदम है और इसे तत्काल वापिस लिया जाय।

विद्यार्थी परिषद् का मानना है कि धर्म आधारित आरक्षण पूर्णत: असंवैधानिक है। यह भारतीयों में एक ऐसी सांप्रदायिक खाई पैदा करेगा जिसे पाटना असम्भव होगा जो कि भविष्य में देश को एक अन्य विभाजन की ओर धकेलेगा। आज अल्पसंख्यको हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम एवं मुस्लिम बहुल जिलों के विकास हेतु अपार धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार के दिशा निर्देश पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंको को अपने कुल ऋण का 15 प्रतिशत भाग मुस्लिमों हेतु चिन्हित करना आवश्यक किया गया है। मुसलमानों हेतु पृथक आई.टी.आई., छात्रावास, कन्या

छात्रावास एवं हज गृह का निर्माण हो रहा है। यह सभी कदम अत्यन्त आपत्तिजनक है।

देशभर में मदरसा शिक्षा में बजट की बेतहाशा वृद्धि न केवल सांप्रादयिक है अपितु भारत की शिक्षा नीति के आधुनिक, वैज्ञानिक, पंथनिरपेक्षता के घोषित उद्देश्य को धूमिल करती है। अ.भा.वि.प. पिछड़े अल्पसंख्यकों से यह आग्रह करती है कि वे अपना अल्पसंख्यकवाद छोड़कर, आधुनिक शिक्षा से राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों।

बहुसंख्यक समाज के छात्रों को 12-14 प्रतिशत ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण मिल पाता है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) मात्र 3 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। संप्रग सरकार ने यह निर्देश जारी किये है कि जो अल्पसंख्यक छात्र देश के 50 प्रतिष्ठित संस्थानों, जैसे आई. आई. एम.,आई.आई. टी. इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करेंगें उनका समस्त शुल्क सरकार देगी। इतना ही नही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई अल्पसंख्यक छात्र कहीं प्रवेश या सेवा के लिये किसी कोचिग संस्थान में प्रवेश लेता है तो उस कोचिग सेन्टर का समस्त शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह सुविधा अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग के छात्र को प्राप्त नही है।

संविधान की धारा 30 के औचित्य पर प्रश्न खड़े हुए हैं इसलिए इस पर राष्ट्रीय चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न समाज विरोधी हित साधनों में हो रहा है। परिषद की मान्यता है कि पंथनिरपेक्षता के मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में समान नागरिकता की अवधारणा एवं राज्य की दृष्टि में सभी के लिए समानता होनी चाहिए, न कि जनसंख्या के किसी विशेष वर्ग का तुष्टीकरण। रोजगार एवं अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में अभाविप यह मांग करती है कि धार्मिक अल्पसंख्यक आरक्षण के सभी प्रस्तावों को पूर्णत: निरस्त किया जाये। ■

देश में एकात्मकता को बढ़ाने का एक प्रयास

-श्रीहरि बोरीकर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों एवं देश के अन्य भागों के छात्रों युवाओं को राष्ट्रीय एकात्मकता के एक सूत्र में पिरोने एवं पूर्वोत्तर राज्यों में पनप रहे अलगाववाद को समाप्त करने के उद्देश्य से 1966 में SEIL प्रकल्प से (Students Experince in Interstate Living) अन्तर्राज्य छात्र जीवन दर्शन नाम से एक प्रकल्प शुरू किया गया था। जिसके अन्तर्गत North East State में से कुछ चुनिंदा छात्रों को देश के दूसरे राज्यों में भ्रमण हेतु लाया जाता है। देश के राज्यों को देखने समझने एवं एकात्मकता का भाव उत्पन्न करने का कार्य इस प्रकल्प द्वारा किया जाता है। जिससे अलगाववाद से चल रही लड़ाई को बल मिलता है। क्योंकि ऐसे छात्र अपने-अपने स्थानों पर लौटकर देश भक्ति अलख जगाते हैं। 1966 से लगातार छात्र देश के अन्य राज्यों में आते हैं कुछ दिन देश भर के कुछ परिवारों में ठहरकर एवं देशभर के प्रमुख लोगों से मिलकर 'अपना देश एक है' ऐसा संदेश देने का प्रयास होता है जिससे भावना जागृत होती है कि कारण ऐसे छात्रों अपने-अपने राज्यों में लौटकर भारत माता की जय व वन्देमातरम् जैसे नारों को साकार करते है जिससे अलगाववाद से चल रही सहायता मिलती है।

वर्ष में एक बार पूर्वोत्तर राज्यों से चुनिंदा 150 छात्र-छात्राओं का तीन भागों में देशभर का भ्रमण करवाया जाता है जिससे देश के अन्य राज्यों में वहां के Culture परम्पराओं को नजदीक से देखने का अवसर मिले। इन यात्राओं का कार्यक्रम देशभर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाएगा तथा देश के प्रमुख हस्तियों से मिला जाएगा जिससे 'यह देश मेरा है' ऐसी भावना उत्पन्न करने में बल मिलेगा। इस प्रकल्प से विद्यार्थी परिषद् ने एक नारे मेरा देश मेरा घर को साकार किया है कि 'देहरादून हो या गोहाटी अपना देश अपनी मांटी' ■

राष्ट्र मण्डल खेल : सज रही दिल्ली उजड़ रहे गरीब

■ अवनीश सिंह

जैसे-जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की घड़िया नजदीक आती जा रही हैं, वैसे-वैसे खेल से जुड़ी परियोजनाओं के आयोजकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन के लिए राजधानी को सुन्दर बनाने के नाम पर 20 लाख से अधिक मजदूरों को काम में लगाया गया है।

सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, निर्माण में लगे मजदूरों के पसीने से दिल्ली चमक रही है और इनके नाम पर सरकार ने उपकर लगाकर अपने खजाने में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इकट्ठा कर ली है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार गरीबी उन्मूलन की योजनाओं से करोड़ों रुपए की धनराशि दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन में लगाई जा रही है।

ज्ञातव्य है कि निर्माण में लगे मजदूर एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार ने वर्ष 2002 में दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया था, जिसकी जिम्मेदारी मजदूरों का बोर्ड में पंजीकरण करवाना और उनके लिए कल्याणकारी योजना बनाकर क्रियान्वित करना है। इसके लिए सरकार को अलग से धनराशि की व्यवस्था भी नहीं करनी है। क्योंकि दिल्ली में हो रहे सभी निर्माण कार्य चाहे वे सरकारी एजेंसी द्वारा किए जा रहे हों या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा, उनके निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रूप में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में जमा करने के निर्देश हैं। अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के निर्माण स्थल पर 20 लाख मजदूरों में से केवल 10 से 15 प्रतिशत मजदूरों का ही पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया गया।

राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन जिसके लिए कई वर्षों से बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने इन खेलों के समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पूरी ताकत और धन झोंक दिया है। एक अनुमान के मुताबिक, इसमें कुल एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा जा रहा है कि यह अभी तक के सबसे महंगे राष्ट्रमण्डल खेल होंगे। यह भी तब जब भारत प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के निम्नतम देशों में से एक है। विश्व भूख सूचकांक में हमारा स्थान इथोपिया से भी नीचे है एवं 77 प्रतिशत के लगभग भारत की जनसंख्या 20 रुपए रोजाना पर गुजर-बसर करने पर मजबूर है।

दूसरी ओर हमारे देश में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे, कुपोषित, आवासहीन एवं अशिक्षित लोग भारत में रह रहे हैं। गरीबों को सस्ता राशन, बिजली, पेयजल, इलाज के लिए पूरी व्यवस्था, बुढ़ापे में पेंशन और स्कूल में पूरे स्थाई शिक्षक और भवन व अन्य सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। फिर सरकार के पास इस बारह दिवसीय आयोजन के लिए इतना पैसा कहां से आया?

गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के करोड़ों रुपए को राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन में लगाए जाने की रिपोर्ट "हाउसिंग एंड लेंड राइट्स नेटवर्क" नामक संस्था ने तैयार की है। संस्था का कहना है कि उसने इस बारे में सूचना का अधिकार कानून के तहत सरकार से जानकारी उपलब्ध की है। इसके मुताबिक गरीबी उन्मूलन की योजनाओं से करोड़ों रुपए की धनराशि दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन में लगाई जा रही है।

यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा करती है और राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए योजनाएं बनाने और धन जुटाने के तरीकों पर सवाल खड़े करती है। रिपोर्ट के अनुसार, समाज के पिछड़े तबकों और गरीब वर्ग की मदद के लिए रखे गए करोड़ों रुपयों की राशि को इन आयोजनों में लगाया जा रहा है। संस्था ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वे इन आरोपों पर गौर कर रहे हैं।

राष्ट्रमण्डल खेलों से सम्बंधित परियोजनाओं के कारण एक लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रमण्डल खेलों पर हो रहा खर्च नियंत्रण के बाहर चला गया है और खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार करने के के लिए पहले प्रस्तावित राशि के मुकाबले में अब 2000 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोत्तरी हुई है।

साथ ही खेलों की वजह से एक लाख से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अक्तूबर में शुरू होने वाली खेलों से पहले 40 हजार और परिवार विस्थापित हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व मानवाधिकार अधिकारी मिलून कोठारी ने तैयार किया है। उन्होंने एक रेडियो वार्ता में बताया कि संस्था के पास इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए स्पष्ट सबूत है। कोठारी के मुताबिक, दिल्ली को एक विश्व-स्तर के शहर के रूप में दिखाने की होड़ में सरकार लोगों के प्रति अपनी कानूनी और नैतिक प्रतिबद्धता को भूल रही है। ■

प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल, अ.भा.वि.प. का एक मित्र संगठन

नेपाल में माओवाद का आन्दोलन सामाजिक या आर्थिक विषमताओं के विरूद्ध न होकर के विस्तारवादी विचार को लेकर चीन द्वारा प्रायोजित है। नेपाली माओवाद भी नक्सलियों व पाकिस्तानपरस्त आतंकवादियों की तरह भारत का विरोधी है। नेपाल में भारत विरोधी आन्दोलन शुरू करने का कार्य भी नेपाल में माओवादियों द्वारा चलाया जा रहा है।

माओवादियों द्वारा ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी कर भारत के कई जिलों को नक्शा में शामिल करना भारत विरोधी पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। भारत के 200 से अधिक जिलों नक्सलियों को पोषित करने का कार्य भी नेपाल के द्वारा ही हो रहा है।

सत्ता पे कब्जे के साथ-साथ नेपाल में माओवादी वहां की संस्कृति परम्पराओं और धर्म को तहस-नहस कर भारत से इनकी दूरियों को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

नेपाल का समाज भारत के साथ अपने परम्परागत सांस्कृतिक सम्बंधों को बनाये रखने क इच्छुक है। माओवाद के चलते उत्पन्न परिस्थितियों से नेपाल का जनसामान्य ही नहीं बल्कि वहां का विद्यार्थी वर्ग भी चिंतित है। ऐसे ही सांस्कृतिक चेतना से युक्त ने विद्यार्थियों का संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल, नेपाली छात्राओं में देशभक्ति, नेपाल की संस्कृति, धर्म की रक्षा के साथ-साथ नेपाल में शिक्षा के प्रति सजग भूमिका में खड़ा है। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् भारत के साथ भी नजदीकी रिश्तों की पक्षधर है।

विश्व विद्यार्थी युवा संघ से सम्बद्ध प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल, अ.भा.वि.प. का एक मित्र संगठन है। ■

लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला जलाया

इलाहाबाद : अभाविप के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.एड. संयुक्त परीक्षा को रद्द किए जाने के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति का कटरा चोराहे पर पुतला दहन किया।

अभाविप के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सुधीर कुमार ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने जान-बूझकर पेपर को लीक करवाया ताकि प्रवेश परीक्षा में व्यवधान डाला जा सके।

प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ त्रिवेदी ने कहा लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू से ही छात्रों के साथ दोषपूर्ण रवैया अपनाया है। एक और जहां 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को परीक्षा से दूर करने का षड्यंत्र रचा गया और फिर पेपर लीक करवाकर छात्रों के साथ कुठाराघात किया गया।

प्रान्त तकनीकी प्रमुख आशुतोष ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तुरन्त जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे नहीं तो बुरे प्रदेश में अभाविप एक वृहद आन्दोलन करने पर मजबूर होगी। ■

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश सहायता केन्द्र

अभाविप ने छात्रों की सहायता के लिए 28 मई से 11 जून तक के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश सहायता केन्द्र शुरू किये। जिसमें अनुमानित तौर पर 25 हजार छात्र-छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा व्यक्तिगत स्तर पर अ.भा.वि.प. कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी समस्या के समाधान का प्रयास किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभाविप द्वारा 16 प्रवेश सूचना केन्द्र लगाए थे। इन केन्द्रों पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश फार्म उपलब्ध कराए गए थे। परिषद् कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम तक इन प्रवेश सहायता केन्द्रों का संचालन किया गया।

4 जून दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सल हमलों के विरोध में प्रदर्शन करते कार्यकर्ता

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश सहायता केन्द्र

आर.एन.आई. नं. 32464/78

अभाविप के नागरिक अभिनन्दन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रो. मेहता, अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद मराठे, राष्ट्रीय महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा, स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं स्वागत समिति के मंत्री प्रदेश मंत्री बृजेश बनकोटी।

सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन करते राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मिलिंद मराठे

कार्यकारिणी को सम्बोधित करते हुए श्री मिलिंद मराठे, साथ में हैं (दाएं) श्री विष्णुदत्त शर्मा (बाएं हैं) राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अम्बेकर

कार्यकारिणी को सम्बोधित करते हुए श्री मिलिंद मराठे,

कार्यकारिणी की बैठक में देशभर से आए प्रतिनिधि